प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 5 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 28 – 04 फरवरी 2019 मूल्य पांच रूपए

जब पूंजीगत प्राप्तियां सकल ऋण है तो क्या इस वर्ष राजस्व व्यय पूरा करने के लिये 14000 करोड़ का कर्ज लिया गया?

बजट दस्तावेजों के मुताबिक

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने जब सदन में 2018 के लिये 41440 करोड़ रूपये के कुल खर्च का बजट रखवा था तब उन्होने वीरभद्र शासन पर यह आरोप लगाया था कि इस शासनकाल में 18787 करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लिया गया है। जयराम ने सदन में आंकड़े रखते हुए खुलासा किया था कि जब भाजपा ने 2007 में सत्ता संभाली थी तब प्रदेश पर 19977 करोड़ का कर्ज था। 31 दिसम्बर 2012 को सत्ता छोड़ते समय यह कर्ज 27598 करोड़ हो गया था। लेकिन अब 18 दिसम्बर को यह बढ़कर 46,385करोड़ हो गया है। जयराम ठाकुर को 46385 करोड़ का कर्ज विरासत में मिला है। इस विरासत के साथ जयराम ने 41440 करोड़ के कुल खर्च का बजट पेश किया था जो अब 3142.65 करोड़ की अनुपूरक मांगे आने के बाद कुल 44582.65 करोड़ पर पहुंच गया है।

मुख्यमन्त्री जयराम ने जब 41440 करोड़ के कुल खर्च का बजट सदन में रखवा था उसमें सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां 30400.21 करोड़ दिखाई गयी थी और राजस्व व्यय 33567.97 करोड़ दिखाया गया था। इस तरह राजस्व व्यय और आय में 3167.76 करोड़ का अन्तर था। राजस्व आय के बाद सरकार पूंजीगत प्राप्तियों के माध्यम से पैसा जुटाती है। सरकार की यह पूंजीगत प्राप्तियां 7764.75 करोड़ रही है। जिनमें 7730.20 करोड़ की प्राप्तियां कर्ज के रूप में है। यह बजट दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से दर्ज है। इस तरह पूंजीगत प्राप्तियों और राजस्व प्राप्तियों को मिलाकर सरकार के पास कुल 38164.96 करोड़ आता है और राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय को मिलाकर कुल खर्च 41439.94 करोड़ हो जाता है। इस तरह सरकार के पास 3274.98 करोड़ का ऐसा खर्च बच जाता है जिसके लिये कोई साधन बजट में नही दिखाया गया है। जिसका सीधा सा अर्थ यह रहता है कि इस खर्च को पूरा करने के लिये पूंजीगत प्राप्तियों के अतिरिक्त और कर्ज लेना पड़ेगा।

अब सरकार 3142.65 करोड़ की अनुपूरक मांगे लेकर आयी है। यह मांगे आने का अर्थ है कि सरकार का इस वर्ष का कुल खर्च बढ़ कर 44582.65 करोड़ का हो गया है। इन खर्चो को पूरा करने क लिये क्या अतिरिक्त उपाय किये गये हैं इसका कोई उल्लेख अनुपूरक मांगों में नही है। स्वभाविक है कि इस खर्च को पूरा करने के लिये या तो सरकार को और कर्ज लेना पड़ेगा या फिर और टैक्स जनता पर परोक्ष/अपरोक्ष रूप से लगाने पड़ेंगे। इस तरह यदि पूंजीगत प्राप्तियों के नाम पर जुटाये गये ऋण और उसके बाद भी खुले छोड़े गये खर्चो और अब आयी अनुपूरक मांगो को मिलाकर देखा जाये तो जो आरोप मुख्यमन्त्री ने वीरभद्र शासन पर अतिरिक्त कर्ज लेने का लगाया था आज यह सरकार स्वयं भी उसी चक्रव्यूह में फंसती नज़र आ रही है। अब अनुपूरक मांगे आने के बाद सरकार का इस वित्तिय वर्ष का कुल राजस्व व्यय बढ़कर 44582.65 करोड़ को पहुंच गया है लेकिन राजस्व की आय तो पूराने 30400.21 करोड़ के आंकड़े पर ही खड़ी है। इससे यह सामने आता है कि इस राजस्व व्यय को पूरा करने के लिये सरकार को 14000 करोड़ का ऋण लेना पड़ा है। यह खुलासा एफआरवीएम अधिनियम के तहत सदन में पेश बजट दस्तावेजों में सामने आता है। इस अधिनियम के तहत बजट दस्तावेजों में व्याख्यात्मक विवरणिका सदन में रखना अनिवार्य है। इस विवरणिका में वित्तिय वर्ष में होने वाला कुल राजस्व व्यय और कुल राजस्व आय के आंकड़े रखे जाते हैं। इसी में पूंजीगत प्राप्तियों का आंकड़ा भी दिखाया जाता है। यह सारी विवरणिका पहले पन्ने पर ही दर्ज रहती है। इस विवरणिका को देखने से सामने आ जाता है कि पूंजीगत प्राप्तियों को सकल ऋण माना जाता है। वर्ष 2018 – 19 में यह पूंजीगत प्राप्तियां सकल ऋणों के रूप में 7730.20 करोड़ दिखायी गयी हैं। इन आंकड़ो को देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि कुल खर्च को पूरा करने के लिये 14000 करोड़ के ऋण की आवश्यकता है क्योंकि कुल आय तो 30400 करोड़ से बढ़ नही पायी है। इस तरह यह सवाल उठना स्वभाविक है कि यह स्थिति कब तक और कितनी देर तक ऐसे चल पायेगी? यह स्थिति सबसे अधिक चिन्ता और चर्चा का विषय बनती है और एक लम्बे समय से ऐसे ही चली आ रही है। लेकिन आज तक इस पर न तो कभी माननीयों ने सदन में कोई चर्चा उठायी है और न ही प्रदेश के मीडिया ने इसे जनता के सामने रखा है।

II. बजट को समझने के लिए मुख्य संकेतक I

(रूपए करोड़ों में)

		वास्तविक 2016-17	संशोधित अनुमान 2017-18	बजट अनुमान 2018-19
क.	राजस्व प्राप्तियां			
	(i) राज्य प्राप्तियां	8756.28	9547.83	10229.12
	(ii) केन्द्रीय प्राप्तियां (including Central Taxes)	14095.80	14332.43	15880.14
	(iii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत अनुदान	3412.25	3833.63	4290.95
	(excluding CSS loans)			
	योग (राजस्व प्राप्तियां)	**26264.34**	**27713.89**	**30400.21**
ख.	राजस्व व्यय			
	(i) गैर योजना	20722.30	23829.28	28302.46
	(ii) योजना	1853.47	1903.49	2189.14
	(iii) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमे	2768.44	3022.45	3076.37
	योग (राजस्व व्यय)	**25344.21**	**28755.22**	**33567.97**
	निवल (राजस्व घाटा /लाभ)	**920.13**	**-1041.33**	**-3167.76**
ग.	पूंजीगत प्राप्तियां			
	(i) सकल ऋण (excluding W&M/	8137.10	7345.56	7730.20
	overdraft but includes net PF receipts)			
	(ii) ऋणों की वसूलियां	29.50	18.59	34.55
	(iii)पूंजीगत विविध प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00
	योग (पूंजीगत प्राप्तियां)	**8166.60**	**7364.15**	**7764.75**
घ.	पूंजीगत व्यय			
	(i) ऋणों की अदायगियां	2272.12	3104.55	3184.20
	(ii) गैर योजना पूंजीगत व्यय	513.15	319.36	475.95
	(iii) योजना पूंजीगत व्यय	5463.15	2764.56	2997.22
	(iv) केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमे	812.42	839.18	1214.59
	योग (पूंजीगत व्यय)	**9060.84**	**7027.65**	**7871.97**

राज्यपाल ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए 'अनन्य' पुरस्कार

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने चंडीगढ़ में जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल द्वारा आयोजित एक समारोह में हिमाचल की तीन विभूतियों को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और नशा तस्करी के खिलाफ उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए अनन्य पुरस्कार-2019 प्रदान किए।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए, राज्यपाल ने कहा कि समाज में प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन्हें पहचानें ताकि अन्य लोग भी उनका अनुसरण करके प्रेरणा ले सकें। उन्होंने कहा कि एक महान विचारधारा अच्छे समाज के निर्माण में सहायक हो सकती है क्योंकि प्रबल विचार समाज की दिशा बदल सकते हैं।

समाज में बढ़ती नशे की समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि यह नशा प्रतिभा का नाश करता है। उन्होंने कहा कि पंजाब में नशा तस्करों पर सख्ती के बाद, जो लोग इस अवैध गतिविधियों में शामिल हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में कदम रखा है, लेकिन हिमाचल सरकार ने ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, जिसके लिए उन्होंने सरकार के प्रयासों एवं पहल की सराहना की। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल सरकार की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस दिशा में जिस गति से काम चल रहा है, उससे भरोसा है कि वर्ष 2022 तक हिमाचल एक प्राकृतिक कृषि राज्य के रूप में उभरेगा।

उन्होंने कहा कि समाज को चरित्रवान व्यक्ति की जरूरत है और ऐसे आयोजन उन लोगों को पहचानने में मददगार होंगे, जिन्होंने जमीनी स्तर पर मानवीय कार्य किया है और कहा कि हमें ऐसे लोगों को समाज में आगे लाना चाहिए। राज्यपाल ने समारोह आयोजित करने के लिए जी नेटवर्क की पहल की सराहना की, जो पूरी तरह से समाज के वास्तविक नायकों को समर्पित है।

राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमीरपुर के मनीष कुमार, बिलासपुर के अजय रतन और चंडीगढ़ के भूपेश जग्गी को सम्मानित किया, त्वचा के लिए काम करने वाली एजेंसी के लिए गुरप्रीत सिंह, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदीप सांगवान, चंबा में पुलिस अधीक्षक डॉ. मोनिका भुटुंगरू ने मादक दवाओं के खिलाफ काम किया। पेडलर्स, स्लम क्षेत्रों में काम करने वाली अमिता मारवा, सामाजिक गतिविधियों के लिए मास्टर कुलदीप शर्मा, गरीबों के लिए काम करने वाले सुनील संधू और हॉकी खिलाड़ी संजीव कुमार को गरीब खिलाड़ियों के साथ काम करने के लिए सम्मानित किया।

हरियाणा के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि समाज में जागरूकता पैदा करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है तथा मीडिया एक ओपीनियन लीडर के रूप में भी काम करता है। उन्होंने समाज के सकारात्मक पहलुओं को उजागर करने के लिए जी नेटवर्क की सराहना की। उन्होंने राज्यपाल को देश में प्राकृतिक खेती के संदेश को फैलाने के लिए धन्यवाद दिया और विशेषकर उत्तरी राज्यों में एक मार्गदर्शक बल के रूप में काम किया।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री किशन कपूर ने इस अवसर पर कहा कि नशाखोरी आज सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। इससे पहले, ड्रग्स के मामले में पंजाब की चर्चा होती थी, लेकिन अब हिमाचल में भी यह चिंता का विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समय रहते राज्य में नशा तस्करी की जाँच के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले एक साल में राज्य में ईमानदारी से प्रयास किए हैं और जन कल्याण की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।

उन्होंने पुरस्कार पाने वालों को बधाई दी और कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से समाज में अच्छा संदेश जाता है और अन्य लोग प्रेरित होते हैं।

सड़े-गले खाद्य पदार्थ बेचने पर होगी कड़ी कार्रवाई

शिमला/शैल। जिलादंडाधिकारी कांगड़ा संदीप कुमार ने बदलते मौसम के दृष्टिगत हैजा, पीलिया जैसे रोगों से बचाव के लिए लोगों से दूषित खाद्य पदार्थ एवं पेयजल के सेवन से बचने और साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की है।

जिलादंडाधिकारी ने लोगों के व्यापक हित में गले-सड़े अथवा बासी, अधपके फल व सब्जियां बेचने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। अपने आदेशों में उन्होंने मिठाइयां, मांस, मछली, चाट, खोया-गिरी, केक, बिस्कुट, ब्रेड एवं दूध इत्यादि बिना ढके खुले में रखकर बेचने को प्रतिबंधित किया है। आदेशों के मुताबिक आइसक्रीम, कुल्फी, शरबत व नींबू पानी जैसे पेय पदार्थो के विक्रेता अपने उत्पादों के विषाणु रहित साफ व स्वच्छ पानी से निर्मित होने का प्रमाणपत्र जीवाणुविज्ञानी से प्राप्त होने पर ही उत्पाद बेच सकेंगे।

उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को किसी इलाके में हैजा की बीमारी से सम्बन्धित अंदेशे पर आवश्यकता जान पड़ने पर वहां रहने वाले सभी व्यक्तियों के हैजारोधी टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कहा है।

जिलादंडाधिकारी संदीप कुमार ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिवार कल्याण अधिकारी, जिला टीबी नियंत्रण अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक, जोनल अस्पलाल के चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं औषधालयों के स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों, नगर निकाय के सफाई निरीक्षकों और तहसीलदारों सहित जिले के समस्त कार्यकारी दंडाधिकरियों को ऐसे बाजारों, दुकानों, भवनों इत्यादि में प्रवेश कर निरीक्षण करने के लिए अधिकृत किया है जहां उपरोक्त पेय अथवा खाद्य सामग्री बनाई व बेची जा रही हो अथवा इसका संग्रह किया गया हो।

उन्होंने इन अधिकरियों को ऐसी सामग्री पाए जाने पर खाद्य सामग्री को इस प्रकार ठिकाने लगाने को कहा है कि जिससे कोई भी इनका सेवन न कर सके। उन्होंने उपरोक्त अधिकारियों को आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया है।

अनुशासित युवा राष्ट्र के पथ पर ले जाते हैं: राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति उसके युवाओं पर निर्भर करती है। युवाओं में एकता और अनुशासन से देश निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) युवाओं के समग्र विकास के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है।

राज्यपाल चंडीगढ़ के टैगोर थियेटर में एनसीसी के हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़ निदेशालय द्वारा आयोजित दिल्ली में गणतंत्र दिवस एनसीसी शिविर से आए कैडेटों की वापसी पर आयोजित सम्मान समारोह के अवसर पर बोल रहे थे।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि 'अपनी स्थापना उपरांत, एनसीसी ने सामाजिक सद्भाव सहित राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया में एक बड़ा योगदान दिया है। एनसीसी ने हमारे लाखों युवाओं के जीवन को उन्हें प्रशिक्षित करके और उनमें देशभक्ति, अनुशासन और निःस्वार्थ सेवा के मूल्यों को विकसित किया है'।

राज्यपाल ने कहा कि भारत एक युवा राष्ट्र है और हमारे युवा हमारी प्रमुख ताकत हैं, इसलिए यदि हम अपने युवाओं की इस विशाल ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाने में सक्षम हों, तो हम आज भी अपने देश के सामने सबसे जटिल चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि एनसीसी हमारे युवाओं की असीम ऊर्जा को दिशा प्रदान करने का एक बहुत ही प्रभावी माध्यम है। उन्होंने दिल्ली में गणतंत्र दिवस शिविर के दौरान इस क्षेत्र के युवा कैडेटों के प्रदर्शन व समर्पण के अतिरिक्त अधिकारियों और प्रशिक्षण कर्मचारियों की ईमानदारी और प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिल्ली में उनके अनुभव पूरे जीवन भर यादों के रूप में उनके साथ रहेंगे। उन्होंने मेजर जनरल आर.एस. मान, अतिरिक्त महानिदेशक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ और उनके चारों राज्यों के सभी समूह कमांडरों को कैडेटों की प्रेरित करने के लिए बधाई दी।

उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेटों की प्रतिभा को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी युवा पीढ़ी कितनी प्रतिभाशाली है। उन्होंने कहा कि केवल वही राष्ट्र प्रगति कर सकता है, जिसके युवाओं में एकता और अनुशासन की भावना हो। उन्होंने कहा कि हमारे देश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन इस भावना की कमी के कारण, विदेशी आक्रमणकारियों ने इसका लाभ उठाया और हम गुलाम हो गए, उन्होंने कहा कि आज, परिस्थितियां अलग हैं और एनसीसी के प्रतिभाशाली युवा देश का भविष्य हैं और उनसे देश को बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना होगा।

इस अवसर पर, एनसीसी कैडेटों ने देशभक्ति से प्रेरित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राज्यपाल ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस एनसीसी शिविर से आए कैडेटों को सम्मानित किया। रक्षा सेवाओं के स्थायी अनुदेशात्मक कर्मचारियों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के सहयोगी एनसीसी अधिकारियों को भी कैडेटों को मार्गदर्शन और प्रेरित करने के लिए सम्मानित किया गया।

इससे पहले मेजर जनरल आर. एस. मान, अतिरिक्त महानिदेशक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ एनसीसी निदेशालय ने इस अवसर पर राज्यपाल का स्वागत किया और नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस एनसीसी शिविर में चयनित 106 कैडेटों के प्रदर्शन और उपलब्धियों के अतिरिक्त एनसीसी की विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी।

कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान 'स्पर्श' के तहत कार्यक्रम आयोजित

शिमला/शैल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर सोलन जिला के नालागढ़ उपमण्डल के बद्दी की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गुल्लरवाला में कुष्ठ रोग निवारण अभियान दिवस आयोजित किया गया। यह जानकारी

जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. गगन दीप राज हंस ने दी। यह कार्यक्रम कुष्ठ रोग जागरूकता अभियान स्पर्श के तहत आयोजित किया गया।

कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. गगन दीप राज हंस तथा खण्ड चिकित्सा अधिकारी नालागढ़ डॉ. के.डी. जस्सल ने कुष्ठ रोग के लक्षणों एवं इसके उपचार के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग असाध्य नहीं है और समय पर जांच एवं चिकित्सा द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कुष्ठ रोग एमडीटी द्वारा पूर्णत: ठीक हो जाता है। उन्होंने आग्रह किया कि कुष्ठ रोगियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करें।

डॉ. गगन दीप ने इस अवसर पर उपायुक्त सोलन द्वारा कुष्ठ रोग निवारण के संबंध में प्रेषित संदेश पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि उपायुक्त द्वारा दिए गए इस संदेश को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में पढ़कर सुनाया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को कुष्ठ रोग एवं इसकी भ्रांतियों के संबंध में जागरूक बनाना है। उन्होंने कहा कि 14 फरवरी, 2019 तक स्पर्श के तहत जिले विभिन्न स्थानों पर सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियां आयोजित की जाएगी।

इस अवसर पर सभी ने प्रदेश एवं देश को कुष्ठ रोग से मुक्त करने एवं कुष्ठ रोगियों से भेदभाव न करने तथा उन्हें उपचार के लिए प्रोत्साहित करने की प्रतिज्ञा भी ली। इस अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य तिथि पर दो मिनट का मौन रख कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

डॉ. जस्सल ने इस अवसर पर कुष्ठ रोग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

कार्यक्रम में कुष्ठ रोग उन्मूलन तथा कन्या भ्रूण हत्या पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। कुष्ठ रोग उन्मूलन वर्ग में रजत ने प्रथम, आयुषी ने द्वितीय तथा रोहित ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में नेहा पहले, संतोष दूसरे तथा लक्की कुमारी तीसरे स्थान पर रही।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
e-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The **Executive Engineer, Electrical Division HPPWD, Una** on behalf of the Governor of Himachal Pradesh invites the item rate bids, in electronic tendering system from the eligible class of contractors registered with HPPWD for the works as detailed in the table.

Sr.No. Name of Work	Estimated Cost (Rs.)	Starting date for downloading bid	Earnest Money	Deadline for submission of Bid	Eligibility of contractor
1.Replacement of Yard lighting in Circuit House at Hamirpur Distt. Hamirpur H.P.	1461808/-		29250/-		B
2. Construction of Polyclinic-cum-Training Hostel in Animal Husbandary complex at Bilaspur District Bilaspur H.P. (SH: Providng E.I. therein).	745795/-		14950/-		C
3. C/O Multipurpose Hall in Village Jhurowal in Tehsil & District Una H.P. (SH: Providing E.I. therein).	615106/-	07.02.2019 (05.30 PM)	12300/-	21.02.2019 (05.00 PM)	C
4. Replalcement of E.I. in Dr. Radha Krishna Govt. Medical College Hospital (Phase-I)	794934/-		16000/-		C
5. Hamirpur Distt. Hamirpur H.P.Providing additional eating & computer point in C.M.O. OfficeHamirpur, Distt. Hamirpur H.P.	613019/-		12300/-		C
6. C/O New Modern Police Statin of State Vigilance & Anticorruption Bureau building at Una Distt. Una H.P. (SH: Providing E.I. therein).	695962/-		14000/-		C

BID OPENING DETAILS:
1. The bids shall be opened on **22.02.2019 at 11.30 Hrs** in the **O/o Executive Engineer, Electrical Division HPPWD, Una** by the authorised officer. In their interest the tenderer are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders.
2. If the happens to be holiday on the date of opening of the bids as specified, the bid will be opened on the next workings day at the same time and venue and no separate notice will given in this regard.
3. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than **120 days** after the deadline date for bid submission.
4. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the employer shall not be liable for any information not received by the bidder's to verify the website for the latest information related to the tender.
5. The competent authority on behalf of Governor of H.P. reserves the right to reject any or all the tenders received without assigning any reason.

Adv. No.-4467/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

हैदराबाद में राइजिंग हिमाचल–2019 रोड शो आयोजित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सरकार एक निवेश मित्र औद्योगिक नीति है, जो राज्य में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों को कई रियायतें और प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर हैदराबाद में राज्य सरकार द्वारा उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से आयोजित 'रोड शो-बिजनेस टू गर्वनमेंट' के दौरान उद्यमियों और निवेशकों को संबोधित करते हुए बोल रहे थे।

जय राम ठाकुर ने उद्यमियों को आश्वासन दिया कि उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य प्रसंस्करण में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों को सरकार लैंड पार्सल के साथ बेहतर कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का निवेशकों तक पहुंचने का यह पहला प्रयास है कि और राज्य में निवेश के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था की बहुत अच्छी स्थिति है और यहां जवाबदेह और जिम्मेदार प्रशासन है, जो राज्य को उद्यमियों के लिए निवेश का पसंदीदा स्थान बनाता है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के उद्यमी मेहनती और प्रतिबद्ध है तथा इस राज्य के उद्यमियों ने दुनिया भर के देशों में अपना नाम बनाया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य का प्रदूषण मुक्त वातावरण यहां सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में निवेश के लिए एक प्रमुख प्लेयर बनाता है। उन्होंने कहा कि फार्मा एक अन्य ऐसा क्षेत्र है, जो निवेश के लिए एक आदर्श स्थान हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आवास, बिजली उत्पादन, सीए स्टोर, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों और इसी तरह से पर्यटन, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक अधोसंरचनात्मक ढांचे जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी लाभदायक साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का प्रदूषणमुक्त वातावरण व शांत पर्यावरण, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता राज्य में आगंतुकों को साहसिक गतिविधियां, वन्यजीव, पर्यावरण, पर्यटन, वेलनेस सेंटर, सांस्कृतिक विरासत, आध्यात्मिकता, पुरातन स्मारक, धार्मिक पर्यटन, स्कीइंग आदि के विभिन्न

विकल्प प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को विश्व स्तर का पर्यटन गंतव्य बनाकर राज्य की आर्थिकी का मुख्य स्त्रोत बनाने के प्रति प्रतिबद्ध है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सेब, प्लम, खुमानी, कीवी, अखरोट और नाशपाती जैसे फलों का एक प्रमुख उत्पादक है तथा इसी के चलते यहां खाद्य प्रसंस्करण और इससे संबद्ध उद्योगों के लिए अपार अवसर प्रदान करता है।

150 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधियों को संबोधित करने के अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने प्रमुख कम्पनियों के सीईओ और उच्च अधिकारियों के साथ बैठकें भी की, जिसमें अपोलो अस्पताल, डॉ. रेड्डीज लैब, रैमकी एनवायरो इंजीनियर्स, आईटीसी लिमिटेड, डीपी चॉकलेट्स, के एसके एनर्जी, माइक्रोमैक्स, एमएनआर ग्रुप, 2-ई नॉलेज, वेंचर्स, नेफोप्लस, डोडला डेयरी आदि ने हिमाचल में निवेश योजनाओं के बारे चर्चा की।

नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक एन.आर. अलुरी ने रिजॉर्ट्स, होटल, सड़कों, सुरंगों और पुलों से संबंधित परियोजनाओं में निवेश करने में रुचि दिखाई। ग्रीनको कंपनी के सीएमडी अनिल चालामाशेट्टी ने कहा कि कंपनी भारत की अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों में से एक है और उन्होंने राज्य में एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं की स्थापना में रुचि दिखाई। रामी एनवायरो इंजीनियर्स के संयुक्त प्रबंध निदेशक मसूद मलिक ने राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन और जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों की स्थापना में रूचि दिखाई। पूजोलोना मशीनरी फैब्रिकेटर्स के निदेशक प्रकाश पाई ने खाद्य प्रसंस्करण और रियल एस्टेट में निवेश करने में रुचि दिखाई। अपोलो हॉस्पिटल्स के संयुक्त प्रबंध निदेशक राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन के विस्तार के साथ-साथ अस्पतालों और निदान केंद्र की स्थापना में निवेश में रूचि दिखाई।

डॉ. रेडीज के प्रबन्ध निदेशक व सह अध्यक्ष जी.वी. प्रसाद ने बद्दी में अपनी औद्योगिक इकाई के विस्तार व 2 ई नॉलेज वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने राज्य में कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने में रूचि दिखाई। नैफरो प्लस के उपाध्यक्ष रोहित सिंह ने राज्य में डाईलेसिस सेंटर स्थापित करने में रूचि दिखाई। डोडला कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक सुनील रेड्डी ने राज्य में डेयरी अधोसंरचना विकास में रूचि दिखाई।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि राज्य में लॉजीस्टिक्स और वेयरहाउसिंग, इत्र (अरोमा), खाद्य प्रसंस्करण, जैव प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन इत्यादि के की अपार संभावना है और राज्य सरकार उद्यमियों को इन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक विद्युत उत्पादक राज्य है तथा राज्य के इम्पलॉयर (नियोक्ता)-कर्मचारियों के बीच हमेशा मधुर संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व वाली वर्तमान राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही थी कि राज्य देश का औद्योगिक हब बनकर उभरे।

बिक्रम सिंह ने कहा कि राज्य में उत्तरदायी और पारदर्शी प्रशासन है, जो राज्य में उद्यमियों को बिना किसी परेशानी के विभिन्न मंजूरियां सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को राज्य में बहुत ही अनुकूल और निवेशक के अनुकूल वातावरण मिलेगा।

अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग मनोज कुमार ने राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में की गई विभिन्न पहलों की विस्तृत जानकारी दी। अपनी प्रस्तुति में, उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में उद्योगों के लिए 1600 एकड़ भूमि बैंक है, जो सोलन में बल्क ड्रग फार्मा पार्क एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ऊना में कांगड़ा में एकीकृत औद्योगिक टाऊनशिप तथा ऊना में टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं।

प्रधान सचिव ऊर्जा, शहरी विकास, टीसीपी और आवास प्रबोध सक्सेना ने शिमला और धर्मशाला में स्मार्ट सिटी के तहत विभिन्न निवेश अवसरों पर प्रकाश डाला। उन्होंने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के अवसरों पर एक प्रस्तुति दी।

हेटेरो ग्रुप के कार्यकारी निदेशक के रत्नाकर रेड्डी ने मुख्यमंत्री का हैदराबाद में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि उनके पास पहले से ही बद्दी क्षेत्र में तीन औद्योगिक इकाइयां हैं और सरकार के उत्तरदायी प्रशासन और निवेशक अनुकूल नीतियों से वह बेहद खुश हैं।

डीपी कोको प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक दुर्गा प्रसाद ने राज्य में निवेश के अपने अनुभव को साझा किया।

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना से स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा: किशन कपूर

शिमला/शैल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने कहा कि प्रदेश के स्थाई निवासी युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना आरम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष आयुवर्ग के युवाओं को 50 लाख रुपये तक की कुल परियोजना लागत वाले उद्यम स्थापित करने के लिए संयंत्र व मशीनरी में 40 लाख रुपये तक के निवेश पर 25 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है। वहीं महिलाओं एवं युवतियों को प्रोत्साहित करने के लिए निवेश पर 30 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है। इस वर्ष इस योजना के लिए 80 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है।

किशन कपूर ने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के नोरबिलिंगा सिद्धबाड़ी में लोगों की समस्याओं को सुनने के उपरांत बोल रहे थे।

खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि इसके अलावा योजना के तहत 40 लाख रुपये के ऋण पर 3 वर्ष के लिए 5 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा। कोई युवा यदि निजी भूमि खरीद कर उद्यम लगाना चाहे तो स्टॉम्प ड्यूटी वर्तमान 6 प्रतिशत के बजाय 3 प्रतिशत की दर से देय होगी। योजना के तहत 62 कार्यो को शामिल किया गया है, जिसमें हेल्थ फिटनेस सेंटर खोलने से लेकर होटल और रेस्तरां जैसे कार्य शामिल हैं।

किशन कपूर ने नोरबिलिंगा सिद्धबाड़ी में लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया तथा शेष समस्याओं के समाधान के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का निपटारा करने को कहा।

कपूर ने कहा कि लोगों की फसलो को बन्दरों व जानवरों से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना शुरू की है। योजना के तहत सौर उर्जा चालित बाड़बन्दी के लिए इस वर्ष 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि अगर किसान समूह इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उसे 85 प्रतिशत के अनुदान का प्रावधान है। उन्होंने लोगों से कृषि विभाग से जानकारी प्राप्त कर योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया।

खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचे और उनके जीवन स्तर में सुधार हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए यह जरूरी है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों का विकास समान गति से हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क, उर्जा, पेयजल, सिंचाई तथा शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में वर्तमान के साथ साथ भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध तरीके से कार्यो को अमलीजामा पहनाया जा रहा है।

किशन कपूर ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों में दालों तथा चीनी के रेट में प्रति किलो 5 रुपए की कटौती की गई है। सरकारी एजेंसियों से दालें व चीनी की खरीद से सरकार को 1 वर्ष में 90 करोड़ की बचत हुई है।

हिमाचल प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में केरल की विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश को भारत सरकार के कार्यक्रम 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' (ईबीएसबी) के तहत केरल के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि दोनों राज्यों में कई समानताएं जैसे सर्वोत्तम साक्षरता दर, अच्छे सामाजिक संकेतक, पर्यटन, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आयुर्वेद आदि हैं। प्रधान सचिव शिक्षा के.के. पंत ने यह ईबीएसबी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा। बैठक में विभिन्न हितधारक विभागों के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया।

पंत ने कहा कि केरल एक बड़ा राज्य है और सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तथा हमारे अधिकारी, छात्र और अन्य संबंधित व्यक्ति केरल राज्य से कई चीजें सीख सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईबीएसबी के तहत सांस्कृतिक आदान-प्रदान, संबंधों को मजबूत करना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना तथा छात्रों के एक्सपोजर विजिट का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने नोडल अधिकारियों से आग्रह किया कि वे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ठोस प्रयास करें क्योंकि यह केरल का दौरा करने के लिए वर्ष का सबसे अच्छा समय और मौसम है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के तहत 10 लाख रुपए प्रदान किए हैं, जिसमें से 5.50 लाख रुपए हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम को प्रदान किए गए हैं। उन्होंने हैंडलूम निगम को केरल में विभिन्न हस्तशिल्प जैसे कि पहाड़ी मूर्तिकला, कांगड़ा और थंका चित्रकला, चंबा रुमाल आदि को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शनी लगाने को भी कहा।

उन्होंने कहा कि आयुर्वेद विभाग को 4.50 लाख रुपये प्रदान किए गए है और विभाग को अपने अधिकारियों/कर्मचारियों और निजी प्रमोटरों को केरल में आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा में सर्वश्रेष्ठ अभ्यास सीखने के लिए भेजना चाहिए क्योंकि यह राज्य इन क्षेत्रों में बहुत आगे है। उन्होंने कहा कि कोच्चि (केरल) में पर्यटन विभाग द्वारा पिछले जनवरी में और इस साल भी पर्यटन मार्ट के दौरान एक प्रदर्शनी लगाई गई थी।

पंत ने कहा कि 45 सदस्यों वाली केरल की एक सांस्कृतिक मंडली ने हिमाचल में डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, सोलन, गेयटी थियेटर शिमला और दाड़लाघाट (सोलन) का दौरा किया था, जिस पर भाषा कला और संस्कृति विभाग द्वारा दो लाख रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि इस सांस्कृतिक मंडली को दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तंजावुर, तमिलनाडु द्वारा प्रायोजित किया गया था।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत दोनों राज्यों के मुहावरों और लोकोक्तियों को दर्शाने वाली पांच सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों का आदान-प्रदान और अनुवाद किया जाएगा। उन्होंने हिमाचल प्रदेश कला और भाषा अकादमी को इस दिशा में उचित कदम उठाने के लिए भी कहा।

राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) एवं राज्य नोडल अधिकारी ईबीएसबी आशीष कोहली ने कहा कि यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत केरल के 50 युवाओं ने हिमाचल का दौरा किया और हमारे राज्य के 50 युवा केरल गए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के 96 मेधावी छात्रों, 72 शिक्षकों और 36-36 एनसीसी और एनएसएस छात्रों को इस वर्ष केरल भेजा जाएगा।

बैठक में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प और हथकरघा निगम, भाषा कला और संस्कृति विभाग, हिमाचल प्रदेश कला और भाषा अकादमी, आयुर्वेद, पर्यटन, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। राज्य परियोजना अधिकारी रेणु ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिये कि आप क्या सोचते हैं, शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं ..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

संसदीय खिायतों का टूना कहीं हिंसा का कारक न बन जाये

मोदी सरकार का इस कार्यकाल का अन्तिम बजट आ गया है लेकिन जिस तर्ज पर यह बजट है उससे एक अब तक चली आ रही संसदीय परम्परा को बदल दिया गया। संसद की परम्परा है कि चुनावी वर्ष में सत्तारूढ़ सरकारअन्तरिम बजट में कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेती है। यह काम आने वाली सरकार के लिये छोड़ दिया जाता है क्योंकि जाने वाली सरकार के पास इतना समय शेष नहीं होता कि वह इन फैसलों को अमली जामा पहना सके। और आने वाली सरकारअपनी नीतियां तथा कार्यक्रम अपनी चुनावी घोषणाओं के अनुसार तय करेगी। इस परिप्रेक्ष में जाने वाली सरकार की नीतिगत घोषणाओं को चुनाव जीतने के प्रलोभनों के रूप में देखा जाता है। 2014 में लोकसभा के परिणाम 16 मई को आ गये थे। इस नाते अब भी तब तक परिणाम आ जायेंगे। इसके लिये मार्च के प्रथम सप्ताह में आचार संहिता लग जायेगी और तब ना कोई फैंसले लिये जायेंगे और न ही लिये हुए फैसलों पर अमल हो पायेगा। इस तरह केवल एक ही फैसला अमल में आ पायेगा और वह है किसानों को छः हजार रू. की राहत पहुंचाना क्योंकि इसे दिसम्बर 2018 से लागू कर दिया गया है।

किसानों को दी गयी इस 17 रूपये प्रतिदिन की सहायता पर किसानों की क्या प्रतिक्रिया रहती है यह आने वाले दिनों में सामने आ जायेगी। अभी ही देश भर के किसान दिल्ली के बाहर जमा हो गये हैं और प्रधानमन्त्री से मिलने का समय मांग रहे हैं। किसानों के बाद आयकर में जो पांच लाख की छूट की बात की गयी है उसमें केवल चतुर्थ श्रेणी के ही कर्मचारी सीधे लाभान्वित होंगे अन्य कर्मचारियों को इससे कोई बड़ी राहत नहीं मिलेगी क्योंकि कुल वेतन की आय पांच लाख से बढ़ जाती है। ऐसे कर्मचारियों को पूर्ववत ही राहत मिलेगी। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल आने वाले समय में यह सामने आयेगा कि सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण के लिये आय सीमा आठ लाख रखी है और आयकर राहत पांच लाख। यह अपने में स्वतः विरोधी हो जाता है। इस पर आने वाले दिनों में सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। क्योंकि आर्थिक आधार पर आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय मे चुनौति दी जा चुकी है और अब सरकार का 5 लाख तक आयकर राहत और आरक्षण के 8 लाख की सीमा से आरक्षण पर सरकार की अपनी ही अस्पष्टता सामने आ जाती है। इसका सर्वोच्च न्यायालय क्या संज्ञान लेता है यह तो आने वाले समय में ही सामने आयेगा लेकिन यह तय है कि सरकार की इस नीति पर बहस अवश्य उठेगी। इस तरह सरकार ने अन्तरिम बजट में नीतिगत फैसले करके सीधे यही इंगित किया है कि आने वाले चुनाव में जीत हासिल करने के लिये सरकार किसी भी हद तक जा सकती है।

अन्तरिम बजट में संसदीय परम्परा से हटने के साथ ही सरकार की नीयत और नीति राम मन्दिर निर्माण को लेकर भी सवालों के घेरे में आ जाती है। जब सरकार से मांग की जा रही थी कि वह इसके लिये अध्यादेश लाये तब प्रधानमंत्री ने कहा कि वह अदालत के फैसले की प्रतिक्षा करेंगे। लेकिन उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में उस जमीन के लिये आवेदन कर दिया जिसे अविवादित कहा जा रहा है। जबकि सरकार के इस अधिग्रहण को ही अदालत में ''अंवाच्छित'' कहा हुआ है। फिर सरकार तो इस प्रकरण में अदालत में पार्टी ही नही है ऐसे में अदालत सरकार के आग्रह को कैसे लेती है और कैसे इस पर त्वरित सुनवाई करती है यह देखना भी रोचक होगा। लेकिन इसी के साथ जिस ढ़ग से दो दो धर्म संसद आयोजित हुये हैं ओर 21 फरवरी को यह निर्माण शुरू कर देनें की घोषणाएं हुई हैं तथा अदालत के जजों के यहां धरने प्रदर्शन करने की चेतावनीयां दी गई हैं उससे एकदम 1992 जैसा माहौल बनने की पूरी पूरी संभावनाएं बन गयी हैं। क्योंकि यह तय है कि साधु समाज का एक वर्ग इस निर्माण की शुरूआत करने आयेगा ही और निर्माण स्थल तथा उसके आसपास धारा 144 लागू ही है। ऐसे में यदि सरकार इन्हे यहां आने से रोकती नही है तब भी कानून और व्यवस्था को लेकर स्वाल उठेंगे। यदि रोकने का प्रयास करेगी तब हिंसा से इसे कोई रोक नही सकेगा। यह सब इससे होना तय लग रहा है। देश में लोकसभा चुनाव से पुर्व समप्रदायिक दंगे भड़कने की आशंका तो अमेरिका की सीनेट में वैश्विक खतरों पर आयी डॉन कोटस की रिपोर्ट में बड़े स्पष्ट शब्दों में व्यक्त की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा लोकसभा चुनावों से पहले अपने हिन्दु एजैण्डा को बढ़ाने के लिये जैसे ही कदम उठायेगी उसी के साथ देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठेगी। अमरीका की सीनेट में चर्चा में आयी इस रिपोर्ट पर भारत सरकार और भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। कोई प्रतिक्रिया न आना तथा धर्म संसद द्वारा 21 फरवरी का निर्माण कार्य शुरू करने के लिये समय तय करना इन आशंकाओं को पुख्ता करता है।

क्योंकि सरकार के पास अर्थिक मोर्चे पर भी कोई बहुत कुछ ऐसा नही है जिसे चुनावों में आसानी से भुनाया जा सके। भारत सरकार के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा पेश की गई वितिय स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार का जो कर्जभार 2014 में था उसमें दिसम्बर 2018 तक 49% की वृद्धि हुई है। इसी के साथ सरकार के सांख्यिकी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार नोटबन्दी के बाद देश में 1.10 करोड़ नौकरियों में कमी आयी है। यह आयोग सरकार के आंकड़ो की निगरानी और उनका आकलन करता है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी 7.4% तक पहुंच गयी है। जो अब तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। सरकार ने इस आयोग की रिपोर्ट को जब जारी नही किया तब इसके अध्यक्ष पी सी मोहनन और सदस्य डा. मीनाक्षी ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। जबकि मई 2017 में नियुक्त हुए इन लोगों का कार्यकाल जून 2020 तक था। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां सरकार की असफलताएं सामने है और चुनावों में इनके मुद्दा बननें की आशंका है। ऐसे में इन मुद्दों को चर्चा से बाहर रखने के लिये सांप्रदायिक हिंसा एक हथियार हो सकती है यह आशंका कोटस की रिपोर्ट में व्यक्त की गई है।

हिमाचल प्रदेश सरकार को दरकार:शिक्षा विस्तार नहीं, गुणवत्ता परक शिक्षा पर दे ध्यान

डॉ. राकेश कपूरः
प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद
एवम सामाजिक कार्यकर्ता

केरल के बाद देश में दूसरे स्थान पर साक्षरता दर , प्रति 1.5 कि. मि पर प्राथमिक विद्यालय, 70 लाख से कम आबादी पर 16 निजी 4 सरकारी विश्वविद्यालय, 1 केन्द्रिय विश्वविद्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, डिज़ीटिज़शन इन एजुकेशन, के दावों से सरोबार अपनी पीठ ठोकने, 4 – 6 – राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाज़ी जाने वाली हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत, निश्चित रूप से चिंता जनक ही नहीं भयावह है। केन्द्र सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय के पर्वक्षण कर्ताओं, स्वतंत्र एजेंसियों के रिपोर्ट प्रकाशन ने हमारी पोलपटटी खोल कर रख दी है। हाल ही में प्रकाशित इस रिपोर्ट में जिन दो प्रमुख तथ्यों को उजागर किया गया है उन पर , चिंता, चर्चा और चिंतन तीनों करने की अविलंब आवश्यकता है। पहली मुफ्त वर्दी, बैग, पुस्तकें, साईकल, पानी की बोतल, मध्यान भोजन, नाम मात्र फीस, सुविधा सम्पन विद्यालयों, मोटी पगार, छुटी और बिना किसी उत्तरदायित्व के नौकरी वाले शिक्षकों की लंबी चौड़ी फौज, तीन तीन निदेशालयों से सजी धजी प्रशासनिक व्यवस्था के बावजूद सरकारी स्कूलों में निरंतर घटती, छात्रों की संख्या, इस के विपरीत, कम तंख्वाह, काम के बोझ से लदे, बिना प्रशिक्षण, अल्पतम योग्यता वाले अध्यापकों से लैस, कुकुरमुतों, की तरह फैले, निजी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु मारामारी, वोह भी मोटी फीस और अन्य कई शुल्क चुका कर अभिभावक यदि निजी शिक्षण संस्थाओं में नौनिहालों को भेजना पसंद कर रहे है, और वहां के शिक्षा स्तर पर विश्ववास कर रहे है तो निश्चित रूप से यह गंभीर विषय है। इस समस्या के निदान हेतु केवल आधिकारिक, या प्रशासनिक ही नहीं सामाजिक चिंतन, चर्चा भी जरूरी है। दूसरी गंभीर समस्या भी इसी से जुड़ी है और वह है सरकारी तंत्र प्रद शिक्षा की गुणवत्ता का अभाव। जब यह सार्वजनिक रूप से विदित हो जाए कि हमारे 8वीं, 9वीं कक्षा के नौनिहाल दूसरी कक्षा के हिंदी अंग्रेजी के पाठ नही पढ़ पाते, जमा गुना, भाग के चौथी कक्षा के प्रशन उन को समझ नही आते। नवीं , दसवीं के छात्र अंग्रेज़ी और हिंदी के मूल व्याकरण, पेए तमए उ का सही प्रयोग नहीं कर पाते बीजगणित, ज्योमिट्री तो दूर की बात, वह गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में भी भेद करने में असमर्थ हैं। वह भी तब जब हम शिक्षा प्रसार, विस्तार और सुविधा सम्पन अति संवेदनशील, कारगार गुरुकुलों द्वारा, योग्य गुरुजनो के माध्यम से गिरिजन, गौजन, ग्रामजन स्थित नौनिहालों को शिक्षा रूपी प्रसाद बांटने वालों की अग्रिम पंक्ति में खड़े होने का दावा ठोक कर पुरस्कारों की लंबी फेहरिस्त अपने पाले में होने से स्वम्भू जगद्गुरु होने तक का दम भर कर अपनी पीठ ठोकने में व्यस्त हैं।

बोर्ड परीक्षाओं में जीरो परिणाम देने वाले विद्यालयों की बढ़ती संख्या, राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं IITJEE, NEET, NEFT में सफल होने वाले प्रादेशिक छात्रों की संख्या और नाम उंगलियों पर गिने जा सकते है इस स्थिति को राष्ट्रहित, प्रदेशहित दोनों में बदलना अवश्यम्भावी है।

गुणवत्तापरक शिक्षा न केवल देश प्रदेश के विकास हित में जरूरी है अपितु आगामी पीढ़ी के राष्ट्र निर्माण निमित भूमिका की मजबूरी है। प्रदेश के शिक्षा ढांचे के सुदृढ़ीकरण हेतु जहां पूर्ववर्ती सरकार के सबको शिक्षा घर पर की जगह केवल सुयोग्य, सुपात्र को सुलभ उच्च शिक्षा ,सब को आधारभूत शिक्षा ,भले ही घर से दूर हो मगर यदि शिक्षण संस्थान हो तो वहां भवन हो , संसाधन हों, अध्यापन व्यवस्था हो, सक्षम अध्यापक हो जो अद्ययन अध्यापन के चाहवान हों। इस प्रदेश में रेवड़ियों की भांति बांटे और अपग्रेड किये जाने वाले स्कूलों की परंपरा पर लगाम लगाया जाना संसाधनों के अपव्यय को रोकने लिए जरूरी, और समाज हित की मजबूरी दोनों है। ऐसे विद्यालयों की घोषणा, या खोलना जहां अध्यापक न हों या न के बराबर हो से जो परिणाम निकले वोह हमारे सामने ही हैं। 8वीं के छात्र कक्षा 2 के पाठ भी नहीं पढ़ पाएं जिन स्कूलों में, उनका होना न होना बराबर। हपतस को गिरल पढ़ा लेने में सक्षम मात्र शिक्षा मित्र, विद्या उपासक, पी टी ऐ, तृतय और चतुर्थ श्रेणी अंकों के बावजूद, कुकुमुततो की तरह स्वीकृत शिक्षा प्रशिक्षण, जे बी टी प्रशिक्षण संस्थानों से निकले शिक्षक सरकारों को वोट और राजनैतिक दलों को फण्ड तो दिलवा सकतें हैं मगर राष्ट्र और राज्य के भविष्य को जो आघात पहुचा देंगे उस की भरपायी कभी नहीं हो सकती। सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत जो मासिक त्रैमासिक रिपोर्ट हर विद्यालय के अध्यापक भर कर निदेशालय भेजते हैं, केवल शाला सिधि के विवरण को ही लें तो शायद मात्र 1% अध्यापक ही स्वयं वो रिपोर्ट भर कर भेजने में सक्षम होंगे, यही कारण है कि अब विद्यालओं में शिक्षण कम और गणेश परिक्रमा पर अधिक जोर है। यदि हम यह चाहते हैं कि सरकार के और सरकारी स्कूलों में छात्र पढ़े और अध्यापक पढ़ाएं तो निशित रूप से इस क्षेत्र में पूर्णतय गुणवत्ता परक, बिना सिफारिश, भेदभाव के नियुक्तियां, योग्यता आधारित प्रशिक्षण, गैर शैक्षिक कार्यो जैसे भवन निर्माण, मध्यान भोजन प्रबंध, हर सर्वेक्षण, चुनाव, आदि से अध्यापकों की मुक्ति, सर्वगुनसम्पन, पारंगता के आधार पर प्रमोशन, प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबंध, नए शिक्षण संस्थान खोलने के बजाए पहले वालों का सुदृकरण, युक्ति करण, तय मानकों पर यह सब प्रयास एक साथ मगर संकल्प से करने की आवश्यकता है। वरना लघु काव्य की यह पंक्तियाँ ''नव नियुक्त शिक्षा मंत्री से बोले पत्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाने को क्या योजना बना रही है सरकार, मंत्री जी तपाक से बोले हमारी नई सरकार इस दिशा में क्रांतिकारी पग उठाएगी हम ने फैसला किया है भविष्य में सरकार सभी स्कूल ऊंचे टीलों पर बनाएगी। को ही चरितार्थ करते दिन बीत जाएंगे।

जिन्हे जार्ज ने खड़ा किया उन्होंने ही जार्ज को धोखा दिया....

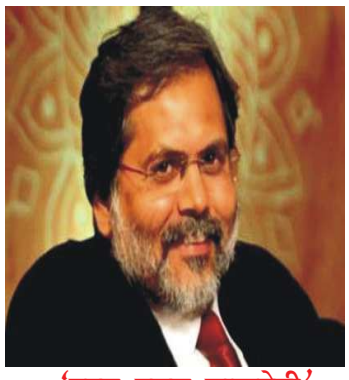

'पुण्य प्रसून बाजपेयी'

तारीख 2 अप्रैल 2009 नीतीश कुमार ने रामविलास पासवान का साथ छोड़कर आये गुलाम रसूल बलियावी का हाथ आपने हाथ में लेकर जैसे ही उन्हें जनतादल यूनाईटेड में शामिल करने का ऐलान किया वैसे ही दीवार पर टंगे तीन बोर्ड में से एक नीचे आ गिरा। गिरे बोर्ड में तीर के निशान के साथ जनतादल यूनाइटेड लिखा था। बाकी दो बोर्ड दीवार पर ही टंगे थे, जिसमें बांयी तरफ के बोर्ड में शरद यादव की तस्वीर थी तो दांयी तरफ वाले में नीतीश कुमार की तस्वीर थी। जैसे ही एक कार्यकर्ता ने गिरे हुये बोर्ड को उठाकर शरद यादव और नीतीश कुमार के बीच दुबारा टांगा, वैसे ही कैमरापर्सन के हुजूम की हरकत से वह बोर्ड एकबार फिर गिर गया। इस बार उस बोर्ड को टांगने की जल्दबाजी किसी कार्यकर्ता ने नहीं दिखायी। पता चला इस बोर्ड को 2 अप्रैल की सुबह ही टांगा गया था। इससे पहले वर्षो से दीवार पर शरद यादव और नीतीश कुमार की तस्वीर के बीच जॉर्ज फर्नांडिस की तस्वीर लगी हुई थी। और तीन दिन पहले ही शरद यादव की प्रेस कॉन्फ्रेन्स के दौरान पत्रकारों ने जब शरद यादव से पूछा था कि जॉर्ज की तस्वीर लगी रहेगी या हट जायेगी तो शरद यादव खामोश रह गये थे।

लेकिन 30 मार्च को शरद यादव के बाद 2 अप्रैल को नीतीश की मौजूदगी में जॉर्ज की जगह लगाया गया यह बोर्ड तीसरी बार तब गिरा, जब प्रेस कन्फ्रेन्स के बाद नीतीश कुमार जदयू मुख्यालय छोड़ कर निकल रहे थे। मुख्यालय में यह तीनों तस्वीरें नीतीश के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के दौरान लगायी गयी थी। उस दिन गुलाल और फूलों से नीतीश के साथ-साथ जॉर्ज और शरद यादव भी सराबोर थे। उस वक्त तीनों नेताओं को देखकर ना तो कोई सोच सकता था कि कोई अलग कर दिया जायेगा या तीनों तस्वीरों को देख कर कभी किसी ने सोचा नहीं था की जॉर्ज की तस्वीर ही दीवार से गायब हो जायेगी। और इसके पीछे वही तस्वीर होगी, जिन्हें राजनीति के फ्रेम में मढ़ने का काम जॉर्ज फर्नांडिस ने किया।

जार्ज फर्नांडिस कितने भी अस्वस्थ क्यों ना हों, लेकिन जो राजनीति देश में चल रही है उससे ज्यादा स्वस्थ्य जॉर्ज हैं, यह कोई भी ताल ठोंक कर कह सकता है। शरद यादव को जबलपुर के कॉलेज से राजनीति की मुख्यधारा में लाने से लेकर लालू यादव की राजनीति को काटने के लिये नीतीश कुमार में पैनापन लाने के पीछे जॉर्ज ही हैं। लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस की जगह नीतीश कुमार को वह जय नारायण निषाद मंजूर हैं, जो लालू यादव का साथ छोड़ टिकट के लिये नीतीश के साथ आ खड़े हुये हैं।

सवाल जॉर्ज की सिर्फ एक सीट का नहीं है, सवाल उस राजनीतिक सोच का है जिसमें खुद का कद बढ़ाने के लिये हर बड़ी लकीर को नष्ट करना शुरु हुआ है। और यह खेल संयोग से उन नेताओं में शुरु हुआ है, जो इमरजेन्सी के खिलाफ जेपी आंदोलन से निकले हैं। हांलाकि सत्ता की राजनीतिक लकीर में जॉर्ज ज्यादा बदनाम हो गये क्योंकि अयोध्या से लेकर गुजरात दंगो के दौरान जॉर्ज बीजेपी को अपनी राजनीति विश्वसनीयता के ढाल से बचाने की कोशिश करते रहे। लेकिन गुजरात दंगो के दौरान नीतीश और शरद यादव में भी हिम्मत नहीं थी कि वह जॉर्ज से झगडा कर एनडीए गठबंधन से अलग होने के लिये कहते। दोनो ही सत्ता में मंत्रीपद की मलाई खाते रहे।

असल में जार्ज अगर ढाल बने तो उसके पीछे उनकी वह राजनीतिक यात्रा भी है जो बेंगलूर के कैथोलिक सेमीनरी को छोड़ कर मुंबई के फुटपाथ से राजनीति का आगाज करती है। मजदूरों के हक के लिये होटल-ढाबा के मालिकों से लेकर मिल मालिकों के खिलाफ आवाज उठाकर मुंबई में हड़ताल-बंद और अपने आंदोलन से शहर को ठहरा देने की हिम्मत जॉर्ज ने ही इस शहर को दी। 1949 में मुंबई पहुंचे जॉर्ज ने दस साल में ही मजदूरों की गोलबंदी कर अगर 1959 में अपनी ताकत का एहसास हड़ताल और बंद के जरीये महाराष्ट्र की राजनीति को कराया तो 1967 में कांग्रेस के कद्दावर एस के पाटिल को चुनाव में हराकर संसदीय राजनीति में नेहरु काल के बाद पहली लकीर खिंची, जहां आंदोलन राजनीति की जान होती है, इसे भी देश समझे। जॉर्ज उस दौर के युवाओं के हीरो थे क्योंकि वह रेल यूनियन के जरीये दुनिया की सबसे बड़ी हडताल करते हैं। सरकार उनसे डरकर उनपर सरकारी प्रतिष्ठानों को डायनामाइट से उड़ाने का आरोप लगाती है। इसीलिये इमरजेन्सी के बाद 1977 के चुनाव में जब हाथों में हथकडी लगाये जॉर्ज की तस्वीर पोस्टर के रुप में आती है, तो मुज्जफरपुर के लोगों के घरों के पूजाघर में यह पोस्टर दीवार पर चस्पा होती है। जिस पर छपा था यह हथकड़ी हाथों में नही लोकतंत्र पर है। और नीचे छपा था- जेल का ताला टूटेगा जॉर्ज फर्नांडिस छूटेगा।

ज़ाहिर है बाईस साल पहले के चुनाव और अब के चुनाव में एक नयी पीढ़ी आ चुकी है, जिसे न तो जेपी आंदोलन से मतलब है, न इमरजेन्सी उसने देखी है। और जॉर्ज सरीखा व्यक्ति उसके लिये हीरो से ज्यादा उस गंदी राजनीति का प्रतीक है, जिस राजनीति को जनता से नही सत्ता से सरोकार होते हैं। इस पीढी ने बिहार में लालू का शासन देखा है और नीतीश को अब देख रहा है। नीतीश उसके लिये नये हीरो हो सकते हैं क्योकि लालू तंत्र ने बिहार को ही पटरी से उतार दिया था। लेकिन लालू के खिलाफ नीतीश को हिम्मत जॉर्ज फर्नांडिस से ही मिली चाहे वह समता पार्टी से हो या जनतादल यूनाईटेड से। लेकिन केन्द्र में एनडीए की सत्ता जाने के बाद बिहार में लालू सत्ता के आक्रोष को भुनाने के लिये जो रणनीति नीतीश ने बनायी, उसमें अपने कद को बढाने के लिये जॉर्ज को ही दरकिनार करने की पहली ताकत उन्होने 12 अप्रैल 2006 में दिखा दी। लेकिन सियासत की बिसात कैसे महाभारत की चौसर पर भी भारी हो चुकी है इसका एहसास तो तब शरद यादव को भी हो चुका होगा। जो 13 वर्ष पहले नीतिश की बिसात पर वजीर बन कर जार्ज को मात देने के लिये तैयार हो गये। और वर्ष भर पहले नीतिश ने सत्ता के लिये मोदी प्रेम तले शरद यादव को भी दरकिनार कर दिया। 2006 को याद किजिये जार्ज के खिलाफ जब पार्टी अध्यक्ष चुनाव में शरद यादव और जॉर्ज आमने सामने खड़े थे। बिलकुल गुरु और चेले की भिंडत। मगर बिसात नीतिश की थी। जार्ज को 25 वोट मिले और शरद यादव को 413 लेकिन चुनाव के तरीके ने यह संकेत तो दे दिये की नीतीश की बिसात पर जॉर्ज का कोई पासा नहीं चलेगा और जॉर्ज को खारिज करने के लिये नीतीश अपने हर पासे को जार्ज की राजनीतिक लकीर मिटाकर अपनी लकीर को बड़ा दिखाने के लिये ही करेंगे।

इसका अंदाजा किसी को नहीं था कि इस तिगडी की काट वही राजनीति होगी जिस राजनीति के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने की बात तीनों ने ही अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत में की थी। इसीलिये जॉर्ज को अस्वस्थ बताकर मुज्जफरपुर से टिकट काटने के बाद नीतीश ठहाका लगा रहे थे कि बिना उनके समर्थन के जॉर्ज चुनाव मैदान में कूदकर अपनी फजीहत ही करायेंगे। वहीं, जॉर्ज अपना राजनीतिक निर्वाण लोकसभा चुनाव लड़कर ही चाहते हैं। इसीलिये जॉर्ज ने पर्चा भरने के बाद अपने मतदाताओं से उन्हें जिताने की तीन पन्नों की जो अपील की है, उसका सार यही है कि जिस तरह गौतम बुद्द के दो शिष्यों में एक देवदत्त था, जो बुद्ध को मुश्किलों में ही डालता रहा, वहीं उनके दोनों शिष्य ही देवदत्त निकले। आनंद जैसा कोई शिष्य जार्ज को तब मिला नहीं और अनथक विद्रोही नेता उसके बाद धीरे धीरे भूलने वाली बिमारी की चपेट में आ गये। अल्जाइमर ने गिरफ्त में लिया तो जार्ज भूल गये नीतिश कौन है। शरद यादव कौन है। इंदिरा गांधी कौन थी। बाल ठाकरे कौन थे। अच्छा है इस दौर में उनकी यादाश्त नहीं थी वर्ना प्रधानमंत्री मोदी को देख गुजरात दंगो के दौर में वाजपेयी के राजधर्म को याद करते और अब के राजधर्म को नकारने के लिये निकल पडते। लंबी खामोशी के बाद जार्ज के निधन की खबर भी जिस खामोशी के साथ आई उसने निद्रा में समायी मौजूदा सियासत को सिर्फ मौत की सूचना भर से जगाया। अच्छा है एनडीए के पांच सारथियों में से वाजपेयी और जार्ज का निधन हो चुका है। दोनों ही आखरी दिनो में सबकुछ भूल चुके थे। जसवंत सिन्हा भी सबकुछ भूल चुके हैं, अल्जाइमर से ग्रसित,। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को खामोश किया जा चुका है। तो अस्वस्थ जार्ज के निधन की खबर भी अस्वस्थ सियासत तले दब गई।

अच्छे दिनों का अहसास कराता बजट

सबसे बड़ा और सराहनीय कदम है पांच लाख तक की आय पर इनकम टैक्स खत्म करना। विपक्ष भले ही इसे चुनावी साल का सियासी कदम कहे लेकिन हकीकत यह है कि यह देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक ठोस कदम है। क्योंकि, एक तो इससे मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा बचेगा जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढेगा

-डॉ. नीलम महेंद्र-

विपक्ष भले ही वर्तमान सरकार के इस आखरी बजट को चुनावी बजट कहे और कार्यवाहक वित्तमंत्री पीयूष गोयल के बजट भाषण को चुनावी भाषण की संज्ञा दे, लेकिन सच तो यह है कि इस आम बजट ने अपने नाम के अनुरूप देश के आम आदमी के दिल को जीत लिया है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, यह सर्वव्यापी, सरस्पर्शी, सरसमवेशी, सर्वोतकर्ष को समर्पित एक ऐसा बजट है जो भारत के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के सपने अवश्य जगाता है जो कितने पूर्ण होंगे यह तो समय ही बताएगा।

यह पहली बार नहीं है जब किसी सरकार ने चुनावी साल में बजट प्रस्तुत किया हो। लेकिन हाँ, यह पहली बार है जब भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली में जहाँ अब तक लगभग हर सरकार चुनावी साल के बजट में केवल आगामी लोकसभा चुनावों को ही ध्यान में रखकर बजट प्रस्तुत करती थीं, वहां इस सरकार ने आगामी दस सालों को ध्यान में रखकर बजट प्रस्तुत किया है।

यही मोदी की शैली है। खुद उनके शब्दों में ''जब मैं काम करता हूँ तो राजनीति नहीं करता।'' और यही उनकी खासियत है कि उनके काम उनके विरोधियों को राजनीति करने लायक छोड़ते नहीं। अब देखिए ना- चुनाव जीतते ही साढ़े चार साल उन्होंने सख्त प्रशासन और नोटबन्दी ,जी एस टी जैसे कठोर फैसले लिए। और अब चुनाव से पहले जी एस टी में छूट, सवर्ण आरक्षण जैसे कदमों के बाद अब बजट में किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों समेत मध्यम वर्ग के लिए सौगातों की बौछार लगा कर अपनी धारदार राजनीति से विपक्ष के वोटबैंक को धराशाही भी कर दिया। जिस मध्यम वर्ग से उन्होंने अपनी सरकार के पहले बजट में कहा था कि उसे अपना ध्यान खुद ही रखना होगा, उस मध्यम वर्ग को चुनावी साल में एक झटके में साध लिया। साथ ही वित्तमंत्री ने यह कहकर कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है ना सिर्फ गरीबों को साधा बल्कि कांग्रेस पर भी प्रहार किया जिनकी सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है।

लेकिन मोदी सरकार के इस बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है यहां तक कि विपक्ष के लिए भी। इस बजट से उन्होंने राहुल के कई चुनावी वादों का जवाब भी दे दिया है। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को हर साल 6 हजार रुपए तीन किश्तों में सीधे उनके खाते में डालने के प्रस्ताव से उन्होंने कांग्रेस की कर्ज माफी योजना पर वार किया है। इससे एक तरफ उन्होंने ना सिर्फ राहुल के मोदी पर किसानों के प्रति असंवेदनशील होने के आरोप को ध्वस्त कर दिया बल्कि रकम सीधे किसानों के खातों में डलवा कर कांग्रेस की कर्जमाफी के लॉलीपॉप की हवा भी निकाल दी। क्योंकि जिस प्रकार एक महीने के भीतर ही मध्यप्रदेश और राजस्थान से करोड़ों के कर्जमाफी घोटाले सामने आ रहे हैं खुद राहुल भी अब समझ चुके हैं कि लोकसभा चुनावों में वो कर्जमाफी का कार्ड नहीं चलने वाला। इसलिए तीन राज्यों में जीत के तुरंत बाद जो राहुल यह कह रहे थे कि 2019 में कर्जमाफी महत्वपूर्ण मुद्दा होगा और मैं नरेंद्र मोदी को तब तक नहीं सोने दूंगा जब तक वो पूरे देश में कर्जमाफी नहीं कर देते आज वो राहुल कर्जमाफी की नहीं बल्कि ''न्यूनतम आय'' की बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इस बजट से राहुल की इस घोषणा की भी हवा निकाल दी। क्योंकि सरकार ने बजट में संभवत: विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना का प्रस्ताव पेश किया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मियों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर माह तीन हजार रुपए पेंशन का प्रावधान है। इसके लिए उन्हें हर महीने मात्र 100 रुपये जमा करने होंगे।

इसके अलावा इस बजट में पहली बार मत्स्य पालन और पशु पालन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड का प्रावधान कर के इन व्यवसायों में रोजगार बढ़ाने की कोशिश की है।

देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर के सेना का मनोबल ऊंचा किया। इसके अलावा प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सौर ऊर्जा जैसे विषयों पर ध्यान निश्चित ही महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम हैं।

लेकिन सबसे बड़ा और सराहनीय कदम है पांच लाख तक की आय पर इनकम टैक्स खत्म करना। विपक्ष भले ही इसे चुनावी साल का सियासी कदम कहे लेकिन हकीकत यह है कि यह देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला एक ठोस कदम है। क्योंकि, एक तो इससे मध्यम वर्ग के हाथ में पैसा बचेगा जिससेस उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढेगा यह पैसा निश्चित ही देश की अर्थव्यवस्था को गति देगा। दूसरा इस प्रकार का कदम कालांतर में देश की अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त करने की दिशा में बुनियादी कदम सिद्ध होगा।

खास बात यह है कि वित्तमंत्री ने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि इतने खर्चों के बावजूद राजकोषीय घाटे को जी डी पी के मात्र 3.4% रखा गया है और यही इस बजट की विशेषता है। उन्होंने बताया कि सात साल पहले राजकोषीय घाटा छ प्रतिशत के उच्च स्तर पर था। 2018-19 में हम इसे 3.4% पर लाने में कामयाब रहे हैं। पिछले वर्ष के कुल बजट का आकार 24,42,213 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस साल 27,84,200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और यह संभव हुआ क्योंकि इन चार सालों में देश को टैक्स से मिलने वाले राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है क्योंकि नोटबन्दी और जी इस टी के बाद लगभग एक करोड़ नए कर दाता जुड़े।

और विपक्ष जितना भी सवाल पूछे कि चार साल पहले क्यों ऐसा लोक लुभावन बजट नहीं पेश किया गया? सच तो वो भी जानते हैं कि देश के बैंक एन पी ए से खाली थे और अर्थव्यवस्था घोटालों और भ्रष्टाचार से। लेकिन आज जब हमारा देश विश्व की तेजी से बढ़ती हुई छठी अर्थव्यवस्था बन गया है तो न सिर्फ ऐसी घोषणाएं की जा सकती हैं बल्कि अमल में भी लायी जा सकती हैं।

देश के विकास का एजेंडा तय करेगा केन्द्रीय बजट

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में केन्द्रीय बजट को ऐतिहासिक करार दिया है। बजट समाज के सभी वर्गो की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आने वाले वर्षो के लिए देश के विकास का एजेंडा तय करेगा। यह एक विकासोन्मुखी बजट है, जो देश को प्रगति और समृद्धि के पथ पर ले जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने बजट में किसानों, गरीबों, महिलाओं, छात्रों, व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लिए की कई बड़ी घोषणाओं की सराहना की है।

बैठक में असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ मजदूरों और श्रमिकों को पेंशन लाभ प्रदान करने तथा आयकर सीमा में 5 लाख रुपये तक की छूट, स्टांप शुल्क में सुधार तथा रक्षा बजट को 3 लाख करोड़ से अधिक करने की भी सराहना की गई।

मंत्रिमण्डल ने केन्द्रीय बजट में नई योजना प्रधानमंत्री किसान निधि की घोषणा का भी स्वागत किया, जिसके तहत 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय समर्थन प्रदान करने के तथा गायों के संरक्षण व संवर्धन के लिए 'राष्ट्रीय कामधेनु आयोग' की स्थापना का भी स्वागत किया है। इस निर्णय से प्रदेश के लगभग सभी किसान लाभान्वित होंगे।

बैठक में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की घोषणा की भी सराहना की गई, जिससे असंगठित क्षेत्र के लगभग 10 करोड़ कामगार लाभान्वित होंगे। यह योजना आगामी पांच वर्षो में विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना होगी, की भी सराहना की गई।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के राजकीय माध्यमिक पाठशाला शामला को उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने तथा शिमला जिला की ही राजकीय उच्च पाठशाला दनयाणा को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा इन पाठशालाओं में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को सृजित व भरने के साथ स्तरोन्नत करने की मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने गोजातीय प्रजनन में सुधार, गोजातीय वीर्य उत्पादन के लिए गोजातीय प्रजनन बैल के उपयोग, प्रसंस्करण, भंडारण व बिक्री के लिए 'हिमाचल प्रदेश बोवाइन ब्रीडिंग बिल, 2019 को प्रस्तुत करने के लिए अपनी मंजूरी दी। इस विधेयक को राज्य विधान सभा में रखा जाएगा।

थीम आधारित पर्यटक सर्किट विकसित करेगी राज्य सरकार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार थीम आधारित पर्यटक सर्किट को उच्च पर्यटक मूल्य (हाई टूरिस्ट वेल्यू), प्रतिस्पर्धा (कम्पीटिटिवनेस) और स्थिरता (सस्टेनेबिलिटी) के सिद्धांतों पर विकसित करने का विचार कर रही है। इस उद्देश्य के लिए सभी हितधारकों की आवश्यकताओं और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करके समन्वित प्रयास किए जाएंगे, जिससे यहां आने वाले पर्यटकों को अच्छे अनुभव मिलेंगे तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने एमईईएचआईटी के ओजस हिरानी और हितेश त्रिवेदी द्वारा हिमाचल प्रदेश के पर्यटन विकास पर प्रस्तुति की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले वर्षो में पर्यटन, भारत सरकार द्वारा आरम्भ की गई स्वदेश दर्शन योजना आरम्भ होने के साथ, पूर्ण परिवर्तन की ओर अग्रसर है। राज्य की विभिन्न जलवायु परिस्थितियां, विविध संस्कृति और प्राकृतिक भव्यता के कारण यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य में स्थित कई बौद्ध मठों के मद्देनजर यहां बौद्ध सर्किट विकसित करने पर विचार कर रही है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य भी विभिन्न कला एवं संस्कृति का केंद्र है और इसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश की कला और संस्कृति में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जहाँ लोग मेलों और त्यौहारों में विश्वास रखते हैं तथा पूरे वर्ष विभिन्न अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। उन्होंने कहा कि इन सर्किटों को विविध सांस्कृतिक गंतव्यों के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां पर्यटक यहां की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का आनंद ले सकेंगे और हिमाचल प्रदेश की कला व संस्कृति के बारे में जान सकेंगे।

उन्होंने कहा कि इन पहलों से राज्य पर्यटन से अधिक राजस्व और रोजगार सृजन में ऊंची छलांग लगाएगा और साथ ही हिमाचल पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षक स्थान बनेगा।

ओजस हिरानी और हितेश त्रिवेदी ने राज्य ने बुद्ध सर्किट, सांस्कृतिक पार्क और शिव धाम के विकास पर प्रस्तुति दी।

इस अवसर पर मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. श्रीकांत बाल्दी, अनिल खाची, रामसुभग सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू, निदेशक भाषा एवं संस्कृति के.के. शर्मा भी अन्यों के अतिरिक्त इस अवसर पर उपस्थित थे।

स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये हिमकेयर योजना आरंभ

शिमला/शैल। प्रदेश के सभी लोगों को गुणवत्तायुक्त एवं बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हिमकेयर योजना आरंभ की है। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी सोलन डॉ. आरके दरोच ने दी। डॉ. आरके दरोच ने कहा कि हिमकेयर योजना में विभिन्न प्रकार के सामान्य व गंभीर रोगों को सहायता के लिए सम्मिलत किया गया है। योजना में लगभग 1800 उपचार प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। वर्तमान में योजना के तहत प्रदेश के 193 अस्पताल पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि सोलन जिला में हिमकेयर योजना के तहत वर्तमान में 24 सरकारी एवं निजी अस्पताल पंजीकृत हैं। इन अस्पतालों में योजना के लाभार्थी निःशुल्क उपचार करवा सकते हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि हिमकेयर योजना के अंतर्गत श्रेणियों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने प्रीमियम की दरें तय की हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले और ऐसे पंजीकृत रेहड़ी-फड़ी वाले जो आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत नहीं हैं, से कोई प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है। एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, 70 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के वरिष्ठ नागरिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ता, मिड डे मील कार्यकर्ता, सरकारी, स्वायत्त संस्थान, समिति, बोर्ड एवं निगम के दिहाड़ीदार कर्मचारी तथा अनुबंध कर्मचारी 365 रुपये का भुगतान कर हिमकेयर योजना का कार्ड बनवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नियमित सरकारी कर्मचारी अथवा सेवानिवृत कर्मचारी नहीं है भी एक हजार रुपये का भुगतान कर हिमकेयर योजना कार्ड बनवा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत लाभार्थी परिवार के लिए योजना अवधि नामांकन एवं नवीनीकरण के अनुमोदन की तिथि से एक वर्ष तक निर्धारित की गई है। नवीनीकरण के लिए लाभार्थियों को उनके मोबाइल नंबर पर संदेश के माध्यम से एक लिंक भेजा जाएगा। इस लिंक द्वारा लाभार्थी निर्धारित प्रीमियम राशि का भुगतान ऑनलाइन कर नवीनीकरण करवा सकता है।

डॉ. दरोच ने कहा कि हिमकेयर योजना में पंजीकरण की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। लाभार्थी www.hpsbys.in पर जाकर अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर और श्रेणी प्रमाण पत्र अपलोड कर नामांकन करवा सकता है। हिमकेयर योजना में अब तक प्रदेश के 2.71 लाख परिवार सम्मिलत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्णय लिया है कि हिमकेयर योजना से जुड़ने के लिए पंजीकरण सुविधा लोकमित्र केंद्र एवं सामान्य सेवा केंद्र में भी उपलब्ध रहेगी। कोई भी लाभार्थी अपने समीप के लोकमित्र के केंद्र में जाकर निर्धारित प्रीमियम के अतिरिक्त 50 रुपये का शुल्क अदा कर योजना से जुड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना के अंतर्गत नामांकन एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया मार्च माह तक जारी रहेगी।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि यह योजना प्रदेश में सभी को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सुनिश्चित बनाएगी। प्रदेश में वर्तमान में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है। सोलन जिला में आयुष्मान भारत के तहत 265 रोगियों का उपचार किया गया है। सोलन जिला में आयुष्मान भारत योजना में 43712 परिवार सम्मिलत हैं। योजना के तहत 14 हजार कार्ड जारी किए गए हैं। जिला में हिमकेयर योजना के तहत अभी तक 411 गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं जबकि 27 रोगियों का उपचार सुनिश्चित बनाया गया है। उन्होंने सभी पात्र व्यक्तियों से हिमकेयर योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है।

सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करेगी जयराम सरकार:विनोद

शिमला/शैल। वर्ष 2018-19 के प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में आयकर की सीमा को 2.50 लाख से बढ़ाकर 5.00 लाख तक किए जाने को महासंघ ने आज तक के देश में प्रस्तुत बजटों में से ऐतिहासिक बताया है जिसमें वेतन भोगियों को एक मुश्त इतनी बढ़ी राहत मोदी सरकार ने देश के कर्मीयों को दी है। महासंघ के संयोजक विनोद कुमार ने कहा है कि 2004 के बजट में आयकर छूट में मिलने वाली स्टैण्डर्ड डिडक्शन को बन्द कर दिया गया था, जिसे मोदी सरकार ने पिछले वर्ष के बजट में 40,000/-की स्टैण्डर्ड डिडक्शन की छूट दी, जो वर्तमान बजट में बढ़ाकर इसे 50,000/-रू किया गया है। स्टैण्डर्ड डिडक्शन का यह मामला कर्मचारी परिसंघ के नेताओं ने 2017 में देश के वित्तमन्त्री अरूण जेटली जो वर्तमान सरकार के विजन डक्यूमैन्ट को जारी करने के लिए शिमला के पीटरहॉफ में आये थे, के ध्यान में लाया गया था, जिसपर केन्द्र सरकार ने 2017-18 के बजट में शामिल किया । इसके साथ देश का मध्यम वर्गीय कर्मचारी 5,000/-से लेकर 15,000/- तक अपनी वार्षिक बचत कर पायेगा क्योंकि 1.50 लाख बचत राशि के साथ 7.00 लाख तक वार्षिक आय वाले कर्मचारी आयकर दायरे से बाहर हो जायेंगे।

महासंघ नेता विनोद कुमार ने कहा है कि मोदी सरकार के प्रस्तुत बजट में रिटायर्मैन्ट ग्रैच्जुयटी को 10.00 लाख से बढ़ाकर 20.00 लाख तक किए जाने को सेवा-निवृत कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए बढ़ा तोहफा बताते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार ने 21,000 तक वेतन पाने वाले मज़दूर/कर्मचारियों को सालाना 7,000/-रू. का बोनस तय करना तथा राष्ट्रीय पैन्शन योजना के अन्तर्गत सरकारी अंशदान को 10 से 14 प्रतिशत तक करते हुए अंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतनमान में 50 प्रतिशत तक बढ़ौतरी कर देश के हर वर्ग को बड़ी राहत और तोहफे दिए हैं जो नरेन्द्र मोदी सरकार की छोटे तथा मध्यम वर्ग के लिए राहत देते हुए उनरकी दूरदर्शिता और जनमानस के प्रति जिम्मेवारी निर्वहन की पुष्टि करता है। महासंघ नेता विनोद कुमार ने कहा है कि केन्द्र सरकार के इस अकल्पनीय बजट के बाद प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में भी कर्मचारियों/मजदूरों की मांगों को जयराम सरकार देगी। मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर प्रदेश के कर्मचारियों की प्रमुख मांग केन्द्रीय सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को प्रदेश में लागू करेगी, इसको लेकर प्रदेश का कर्मचारी आश्वस्त है। इसके साथ-साथ प्रदेश के दैनिक भोगी कर्मचारियों और श्रमिकों के नियमितीकरण की अवधि 3 साल और अनुबन्ध पर नियुक्त कर्मचारियों की अवधि 2 साल करने की भी कर्मचारी उम्मीद लगाये हैं।

पुलिस कर्मचारियों व पुलिस पैंशन धारकों के लिए चम्बा, सिरमौर व ऊना में पुलिस बल कैन्टीन शुरू

शिमला/शैल। राज्य में पुलिस कर्मचारियों व पुलिस पैंशन धारकों के कल्याण के लिए एवं उन्हें बाजार से कम दामों पर सामान उपलब्ध करवाने के लिए पुलिस विभाग कृत संकल्प है। इस दिशा में केन्द्रिय पुलिस बल कैन्टीन प्रणाली को लागू करते हुए 15 दिसम्बर 2018 में शिमला, मण्ड़ी, धर्मशाला व डरोह में चार केन्द्रिय पुलिस बल कैन्टीनों का शुभारम्भ किया गया था। इसी कड़ी में विभाग ने इस प्रणाली का विस्तार करते हुए 03 जिलों चम्बा, सिरमौर व ऊना में पुलिस बल कैन्टीन खोलने का कदम उठाया है।

दिनांक 01.02.2019 को जिला सिरमौर के नाहन में पुलिस लाईन परिसर में अजय कृष्ण शर्मा पुलिस अधीक्षक सिरमौर ने पुलिस बल कैन्टीन का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर सिरमौर जिला व छठी भारतीय रिजर्व वाहिनी गढ़ीवाला के पुलिस अधिकारी व भारी संख्या में पुलिस जवान उपस्थित थे। आगामी कल जिला ऊना व चम्बा में पुलिस कैन्टीन का शुभारम्भ किया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी है।

यहां यह कहना उचित होगा कि दिनांक 15 दिसम्बर 2018 को शिमला, मण्ड़ी, धर्मशाला व डरोह में खोली गई पुलिस बल कैन्टीनों में भारी बिक्री होना पाई गई है। 15 दिसम्बर 2018 से 31 जनवरी 2019 तक इन चारो कैन्टीनों में कुल 59,24,572 रू. का विक्रय हुआ है। (धर्मशाला में 16,24,958/-रू., शिमला में 14,02,684/-, मण्ड़ी में 17,96,930/- व पी.टी.सी. में 11,00,000/- रू.)। केन्द्रिय पुलिस बल कैन्टीन प्रणाली को लागू करने से प्रदेश के पूरे पुलिस बल व पुलिस के सेवा निवृत कर्मचारियों में खुशी की लहर है।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय अंतरिम बजट को बताया ऐतिहासिक

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए अंतरिम बजट 2019-20 को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के सभी वर्गों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आने वाले

वर्षों के लिए देश के विकास का एजेंडा तय करेगा। उन्होंने कहा कि यह एक विकासोन्मुखी बजट है, जो देश को प्रगति और समृद्धि के पथ पर ले जाएगा।

उन्होंने कहा कि बजट में किसानों, गरीबों, महिलाओं, छात्रों, व्यापारियों और मध्यम वर्ग के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं में 12 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए प्रत्यक्ष आय समर्थन के साथ ही 10 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना तथा आयकर सीमा में 5 लाख रुपये तक की छूट, स्टांप शुल्क में सुधार तथा रक्षा बजट को 3 लाख करोड़ से अधिक रखा गया है जो रक्षा क्षेत्र के लिए अभी तक उच्चतम बजटीय आवंटन है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के लिए उच्च बजटीय आवंटन और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए 58,166 करोड़ रुपये की धनराशि का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। उन्होंने 1.5 करोड़ मछुआरों के कल्याण के लिए अलग से मत्स्य पालन विभाग बनाने के निर्णय का भी स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजना 'प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि' पीएम-किसान की घोषणा किसान परिवारों को, जिनकी 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि है, प्रति वर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय समर्थन प्रदान करने के लिए की गई है। गायों के संरक्षण व संवर्धन के लिए 'राष्ट्रीय कामधेनु आयोग' की स्थापना भी एक स्वागत योग्य कदम है।

उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ मजदूरों और श्रमिकों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए एक नई योजना 'प्रधानमंत्री श्रम-योगी मानधन' की घोषणा की गई है, जो अगले पाँच वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी पेंशन योजनाओं में से एक होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन व्यक्तियों की सकल आय 6.50 लाख रुपये है, उन्हें किसी भी अतिरिक्त आयकर नहीं देना होगा, बशर्ते उन्होंने भविष्य निधि, निर्दिष्ट बचत और बीमा आदि में निवेश किया हो। अंतरिम बजट में 2 लाख रुपये शिक्षा ऋण में ब्याज पर, राष्ट्रीय पेंशन योजना योगदान, वरिष्ठ नागरिकों पर चिकित्सा बीमा और चिकित्सा व्यय आदि में भी अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है।

"भव्य भारत" के सपने को साकार करेगा बजट:किशन कपूर

शिमला/शैल। खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने जन कल्याणकारी और विकासोन्मुखी बजट पेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि यह बजट भव्य भारत के निर्माण करने वाला है।

किशन कपूर ने कहा कि बजट में सभी वर्गों की बेहतरी का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि मध्य वर्ग, गांव, गरीब और किसान के लिए यह एक बेहतरीन बजट है। बजट में आयकर में छूट की सीमा पांच लाख करने की घोषणा एक सराहनीय कदम है। वहीं निवेश के साथ 6.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगाने का निर्णय भी बड़ा साहसिक फैसला है।

उन्होंने कहा कि बजट में नई योजना 'प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि' की घोषणा की गई है, जिसके तहत 2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये उनके बैंक खातों में डाले जाएंगे। इस निर्णय से जहां देश के 12 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित होंगे वहीं प्रदेश के अधिकतम किसानों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने गायों के संरक्षण व संवर्धन के लिए 'राष्ट्रीय कामधेनु आयोग' की स्थापना की घोषणा की भी सराहना की है।

किशन कपूर ने कहा कि इस बार रक्षा बजट का आबंटन तीन लाख करोड़ रुपये किया गया है। रक्षा बजट में पहली बार इतनी बड़ी धन राशि का आवंटन किया गया। इससे देश की सीमाएं मजबूत होंगी, जिससे पूरी दुनिया में भारत का नाम होगा। उन्होंने कहा कि आंखों में देश के स्वर्णिम भविष्य का सपना लेकर आजादी की लड़ाई में कूदे बहादुर नौजवानों के सपने साकार करने के लिये मोदी सरकार ने प्रतिबद्धता से कार्य किया है।

उन्होंने कहा कि यह न्यू इंडिया के सपनों को साकार करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये प्रधानमंत्री ''श्रम योगी मानधन योजना'' की घोषणा एक ऐतिहासिक पहल है। इसके तहत श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। इससे लोगों के जीवन में सुरक्षा और सम्मान तय होगा।

किशन कपूर ने बजट का विरोध करने वाले नेताओं पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने 60 साल राज किया वे अब बगलें झांक रहे हैं। इस सरकार ने देश के गरीबों के लिए इतना किया है जिनता पिछले 65 साल में नहीं हुआ है। विरोध करने वालों के पास कहने के लिये कुछ बचा नहीं है, बस विरोध के लिये विरोध कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 270 परीक्षण में से 86 मामले पॉजिटिव

शिमला/शैल। स्वाइन फ्लू के लक्षण, कारण और उपचार के बारे में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए

ताकि मरीज को तत्काल और समय पर उपचार उपलब्ध कराया जा सके। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर राज्य में स्वाइन फ्लू के मामलों को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस बीमारी के लक्षणों व रोकथाम के उपायों के बारे लोगों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। उन्होंने विभाग को करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव मामलों का पूर्ण विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि समय रहते बीमारी की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय किए जा सकें। उन्होंने कहा कि विशेष चिकित्सा दलों को उन क्षेत्रों में तैनात किया जाना चाहिए जहां अधिकतम मामले सामने आए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार न केवल दवाओं की उपलब्धता को लेकर संवेदनशील है, बल्कि बुनियादी ढांचे को भी मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि शिमला में 12 बेड की सुविधा वाला एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और मौजूदा चार बेड सुविधाओं के साथ एक और आईसीयू को जोड़ा गया है ताकि इससे प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि स्वाइन फ्लू की घटनाओं में आई गिरावट के बावजूद भी राज्य सरकार ने आईजीएमसी शिमला में 8000 उन्नत कैप्सूलों का स्टॉक उपलब्ध करवाया गया है ताकि स्वाइन फ्लू को फैलने से रोका जा सके।

जय राम ठाकुर ने कहा कि दवाओं का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए ताकि रोगियों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा कि उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जहां से एच 1 एन 1 संक्रमण के अधिक मामले सामने आए हैं।

मुख्यमंत्री ने स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए प्रभावित रोगी के परिवार के सदस्यों की प्रतिरक्षा दवाईयां उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू के 270 परीक्षण किए गए, जिनमें से 86 मामले पॉजिटिव पाए गए।

2019-20 के लिए राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत पर नियंत्रित:सीआईआई

शिमला/शैल। पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत 2019-20 के बजट ने अर्थव्यवस्था में मांग और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सही बिंदुओं को स्पर्श किया है। किसानों, मध्यम वर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे समाज के प्रमुख उपभोग वर्गों को दृढ़ता से संबोधित करते हुए, इसका उद्देश्य आय को स्थिर करना और कमजोर लोगों के लिए जोखिम कम करना है। राजकोषीय घाटे को नियंत्रण में रखने के लिए वित्त मंत्री की प्रशंसा की जानी चाहिए। बजट दर्शाता है कि अच्छी राजनीति अच्छे अर्थशास्त्र में तबदील हो सकती है।

सरकार ने वर्षों से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं और बजट किसानों के लिए प्रत्यक्ष आय हस्तांतरण प्रदान करने के लिए एक उल्लेखनीय पहल करता है। किसानों को उनके फायदे पहुंचाने से भविष्य में सभी गरीब नागरिकों के लिए एक बुनियादी आय योजना में विस्तार करने के लिए आधार तय होगा, जो उद्योग के सुझावों के अनुरूप है। बजट में एक महत्वपूर्ण कदम औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है जो श्रम सुधारों के लिए पहल को प्रोत्साहित करेगा। मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए कर राहत अर्थव्यवस्था में समग्र विश्वास को भारी बढ़ावा देगी।

सरकार ने 2030 में बुनियादी ढांचे, सामाजिक क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी और स्थिरता जैसे प्रमुख विकास वाहकों के आधार पर देश के लिए एक महत्वाकांक्षी और अपेक्षाओं से भरपूर दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार की है। ये सीआईआई के भारत @ 75 कार्यक्रम के तहत वर्णित कई तथ्यों से जुड़े हैं, जो भारत के आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और नैतिक शक्ति को दर्शाते हैं।

सचित जैन, चेयरमैन, सीआईआई उत्तरी क्षेत्र, यह सराहनीय है कि वित्त मंत्री 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे को 3.4 प्रतिशत पर नियंत्रित करने में सक्षम रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र और मध्यम वर्ग को प्रदान किए गए प्रोत्साहन और समर्थन के बावजूद सिर्फ 0.1 प्रतिशत का ही फर्क पड़ा है। दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों के लिए 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष आय ट्रांसफर के माध्यम से कृषि आय स्थिरता पर ध्यान देना एक स्वागत योग्य कदम है और कृषि के साथ जुड़े जोखिम को कम करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तरी राज्यों का कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय कृषि जीडीपी में लगभग एक तिहाई योगदान देता है, इससे छोटे और सीमांत किसानों को बहुत लाभ होगा और उनको प्रोत्साहन मिलेगा।

केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया- समीर गुप्ता, डिप्टी चेयरमैन, सीआईआई उत्तरी क्षेत्र

वित्त मंत्री द्वारा अगले 8 वर्षों में भारत की इकोनॉमी 10 ट्रिलियन डॉलर की होने का दृष्टिकोण एक स्वागत योग्य कदम है। असंगठित क्षेत्र और पेंशन के लिए सामाजिक सुरक्षा योगदान श्रमिकों को बहुत मदद करेगा और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती से स्थापित करने में लंबा रास्ता तय करेगा। आयकर की छूट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने से उपभोक्ताओं/लोगों के हाथों में खर्च करने योग्य आय में वृद्धि होगी।

शहरी विकास मंत्री ने गृहिणी सुविधा योजना के तहत 207 गैस कुनेक्शन किए वितरित

शिमला/शैल। प्रदेश में महिला सशक्तिकरण एवं पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरम्भ की गई है। ऐसे परिवार जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं हैं को इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

यह जानकारी शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री ने शाहपुर के 39 मील सामुदायिक भवन में निःशुल्क गैस कनेक्शन एवं चेक वितरण समारोह में उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए दी।

शहरी विकास मंत्री ने कहा कि अब तक जिला काँगड़ा में इस योजना के अंतर्गत 8500 गृहिणियों को यह गैस कनेक्शन वितरित किये जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना से जहां महिलाओं को ईंधन लकड़ी एकत्रित करने के झंझट व चूल्हे के धुएं से छुटकारा मिला है, वहीं वन कटान पर रोक लगाने में मदद मिल रही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समाज के सभी वर्गों विशेषकर कमजोर वर्गों के उत्थान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण महिलाओं को पंचायत स्तर पर संगठित कर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने व उनके उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाने तथा कौशल विकास प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नई सशक्त महिला योजना आरम्भ की गई है।

इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री ने शाहपुर विधानसभा की लगभग 15 पंचायतों की पात्र 207 गृहिणियों को निःशुल्क गैस कनेक्शन व 47 लाभार्थियों को 6 लाख सात हजार के चेक वितरित किये।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.co.in

लोस चुनावों में आसान नही होगी राठौर की राह वीरभद्र के तेवरों से उभरे संकेत

शिमला/शैल। क्या कांग्रेस के नव नियुक्त अध्यक्ष कुलदीप राठौर पार्टी को लोकसभा चुनावों में पूरी एकजुटता के साथ उतार पायेंगे? क्या कांग्रेस इन चुनावों में 2014 के मुकाबले अपना प्रदर्शन सुधार पायेगी? यह सवाल

कांग्रेस के भीतर एक बार फिर उभरते नजर आ रहे हैं क्योंकि वीरभद्र सिंह ने अब प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीरभद्र सिंह ने मनजीत ठाकुर के अध्यक्ष होने पर यह कहकर सवाल उठाया है कि उसने विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ काम किया है जिसके कारण वहां हार मिली। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को पद संभाले काफी अरसा हो गया है और विधानसभा चुनाव भी 2017 में हुए थे। ऐसे में आज वीरभद्र सिंह द्वारा यह मुद्दा सार्वजनिक तौर पर उस समय उठाया जाना जब पार्टी के नये अध्यक्ष राठौर ने भी संगठन के भीतरी मामलों को ऐसे न उठाने के निर्देश जारी किये हुए हैं। इस परिपेक्ष में राजनीतिक विश्लेष्कों के लिये कांग्रेस के भीतर उभरती यह स्थिति एक रोचक विषय बन जाती है।

वीरभद्र का यह एतराज उस समय सामने आया है जब युवा कांग्रेस ने अभिषेक राणा के खिलाफ अनुशासनात्मक कारवाई करते हुए उनसे युवा कांग्रेस की जिम्मेदारीयां छीन ली हैं। अभिषेक राणा सुजानपुर के विधायक राजेन्द्र राणा के बेटे हैं और वीरभद्र सिंह अभिषेक राणा को हमीरपुर से लोकसभा के लिये भावी प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। जब अभिषेक ने लोस टिकट के लिये आवदेन किया था तब वह इसके लिये वीरभद्र सिंह का आर्शीवाद लेने विशेष रूप से गये थे। ऐसे में जिस व्यक्ति के खिलाफ उसका संगठन एक ओर अनुशासन की कारवाई कर रहा हो और दूसरी ओर पार्टी का वरिष्ठतम नेता छः बार मुख्यमन्त्री रह चुका व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की उम्मीदवारी का सार्वजनिक ऐलान करे तो निश्चित रूप से यह सोचना ही पड़ेगा कि क्या यही पार्टी की एक जुटता और अनुशासन है। यहां यह उल्लेख करना भी संगत हो जाता है कि वीरभद्र सिंह के खिलाफ चण्डीगढ़ के ईडी कार्यालय मे मनीलॉड्रिंग की शिकायत करने वाले भी राजेन्द्र राणा ही थे। बाद में राजेन्द्र राणा ने इस शिकायत को यह कहकर वापिस लिया था कि ''किसी ने उनके नाम से यह शिकायत कर दी थी''। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राजेन्द्र राणा और वीरभद्र के सियासी रिश्तो की गहनता कुछ अलग ही है।

लेकिन इस समय पार्टी को लोकसभा चुनाव को सामना करना है। वीरभद्र एक लम्बे समय से सुक्खु को अध्यक्ष पद से हटाने की मांग कर रहे थे। इस मांग के समर्थन में जब आनन्द शर्मा ''वीरभद्र सिंह, मुकेश अग्निहोत्री और आशा कुमारी जैसे सारे वरिष्ठ नेताओं ने इकट्ठे होकर प्रयास किया सुक्खु हट गये और राठौर को कमान संभाल दी गयी। राठौर के पदग्रहण करते समय जो कुछ घटा वह सबके सामने है। उस पर जांच बिठाई गयी थी जिसकी रिपोर्ट आ गयी है अब यह सामने आना है कि इस पर क्या कारवाई होती है। जबकि चर्चा यहां तक है कि जो लोग इस घटना की पृष्टभूमि मे थे उनमें से किसी को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी तक भी मिल सकती है। राठौर ने यह तो कहा ही है कि जिन कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व में न्याय नही हुआ है उनके साथ न्याय किया जायेगा और संगठन मे कुछ नये लोगों को जिम्मेदारीयां दी जायेंगी। तय है कि यह सबकुछ यदि लोस चुनावों से पहले होता है तो इसका संगठन पर प्रभाव बहुत ज्यादा सकारात्मक नही रहेगा।

इस समय लोकसभा चुनावों में संगठन की परीक्षा सीटें जीतने के रूप में होगी। यह सीटें जीतने के लिये पार्टी को पूरी आक्रामकता के साथ चुनाव में आना होगा और आक्रमकता मुद्दों पर निर्भर करेगी। अबतक कांग्रेस की जो आक्रामकता उसके आरोप पत्र के माध्यम से सामने आ चुकी है उसके आधार पर चुनावी सफलता मिल पाना सम्भव नहीं होगा। फिर वीरभद्र तो जयराम सरकार को अभी और वक्त दिये जाने की बात कह चुके है। संभवत: वीरभद्र के इसी निर्देश के कारण कांग्रेस का आरोप पत्र बहुत कमजोर दस्तावेज के रूप में सामने आया है। ऐसे में क्या पार्टी हिमाचल में केवल राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर ही चुनाव में जायेगी? यदि ऐसा होता है तो अभी तक प्रदेश का कोई भी नेता ऐसा सामने नहीं आया है जिसने राष्ट्रीय मुद्दों पर पूरी गहनता और गम्भीरता से अध्ययन किया हो। इसी के साथ यह भी रहेगा कि अभी प्रदेश सरकार को चार साल सत्ता में रहना है और लोगों को इसी से अपने काम करवाने हैं। इस परिदृश्य में नये अध्यक्ष की चुनौतियां बहुत बढ़ जाती है क्योंकि इस समय वीरभद्र सिंह ने जिस तरह युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है उसका निश्चित रूप से युवा कार्यकर्ताओं पर असर पड़ेगा। इंटक में पहले से ही धढ़ेबन्दी खुलकर सामने आ चुकी है।

ऐसे में चुनावी सफलता के लिये उम्मीदवारों का चयन ही एक मात्र विकल्प रह जाता है। उसमें भी वीरभद्र हमीरपुर और कांगड़ा से अभिषेक राणा और सुधीर शर्मा की उम्मीदवारी का ऐलान कर चुके हैं। इनमें से सुधीर शर्मा ने तो टिकट के लिये आवेदन तक नही किया है। मण्डी से चुनाव लड़ने को लेकर वीरभद्र कई बार अपने ब्यान बदल चुके हैं। बल्कि सबसे पहले जब उन्होंने यह कहा था कि कोई भी मकरझण्डु चुनाव लड़ लेगा तो उसी से उनकी नीयत और नीति सामने आ गयी थी। इसी तरह जब हमीरपुर से सुक्खु की उम्मीदवारी को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था तब उन्होने यहां तक कह दिया था कि वह नही समझते की हाईकमान में कोई इतना मूर्ख होगा। इस तरह यदि कांग्रेस के अन्दर अब तक जो कुछ घटा है और उसमें वीरभद्र सिंह की भूमिका किस तरह की रही है उसका निश्पक्ष आंकलन करने से यही सामने आता है कि यदि मण्डी से वीरभद्र स्वयं या उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव में आता है तभी पूरे चुनाव में कांग्रेस की गंभीरता और ईमानदारी झलकेगी अन्यथा नही। क्योंकि इस समय वीरभद्र परिवार

राजनीति की जिस ऐज और स्टेज पर आ खड़ा है वहां से वह अब कोई चुनाव हारने के लिये नही लड़ेगा। यही स्थिति हमीरपुर मे मुकेश अग्निहोत्री की है। इस तरह यदि कांग्रेस इन दोनों को चुनाव लड़ने के लिये तैयार कर पाती है तो प्रदेश का पूरा चुनावी परिदृश्य ही बदल जायेगा अन्यथा कांग्रेस को कोई सफलता मिलना आसान नही होगा। कुलदीप राठौर की राजनीतिक समझ की परीक्षा भी इसी से हो जायेगी अन्यथा बाद में सारा ठीकरा उनके सिर आसानी से फोड़ दिया जायेगा।

जनमंच कार्यक्रमों की प्रासंगिकता सवालों में

शिमला/शैल। जनमंच जयराम सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है लेकिन विपक्ष इसे कई बार झण्ड मंच करार दे चुका है। अभी राजधानी में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और शिमला की मेयर के बीच हुआ संवाद जिस तर्ज पर पहुंच गया था उससे इस कार्यक्रम की उपादेयता पर फिर से प्रश्नचिन्ह लगने शुरू हो गये हैं। यही नही यह सवाल भी उठने लग पड़ा है कि क्या इस मंच के माध्यम से सही में गंभीर समस्याओं का हल निकल पा रहा है? क्योंकि इस जनमंच से पहले इसके लिये जो प्री मंच खलीणी में आयोजित किया गया था उसमें एक विषय आया था कि पटवार खानों में बिजली का मीटर किसके नाम पर लगाया जाये। क्योंकि इस समय प्रदेशभर में पटवार खानों में यह मीटर पटवारी के नाम पर लगाया जाता है। जब पटवारी का तबादला हो जाता है तब वह इसे अपने नाम से कटवा देता है। फिर उसके स्थान पर आने वाला पटवारी नये सिरे उसी प्रक्रिया से गुजरता है और कई-कई दिन तक पटवारखानों में बिजली बाधित रहती है।

प्री मंच में इस समस्या पर लम्बी चर्चा हुई लेकिन इसका कोई समाधान नही निकला। विद्युत और राजस्व विभाग दोनों के पास इसका कोई ठोस हल नही था। लेकिन जब इस प्री मंच के बाद जनमंच आयोजित हुआ तब इस समस्या को वहां पर उठाया ही नही गया जब कि इस मंच पर अधिकारियों के साथ सरकार के दो वरिष्ठ मन्त्री मौजूद थे। इससे यह सामने आता है कि इस मंच पर गंभीर और बुनियादी समस्याओं के लिये कोई स्थान नही है जबकि पटवार खानों में बिजली के मीटरों की यह समस्या पूरे प्रदेशभर की है। लेकिन आज तक

कंही से भी यह समस्या चर्चा में नही आयी है और अब जब प्री मंच में यह उठी तो इसे फिर पूरे जनमंच पर आने ही नही दिया गया। इससे जनमंच कार्यक्रमों की प्रसांगिकता पर सवाल उठने लग पड़े है।

जयराम सरकार के महत्वकांक्षी जनमंच कार्यक्रम के तहत राजधानी में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सरेआम सबके सामने नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट पर ही भड़क गए। कुसुम सदरेट भाजपा की ही महापौर हैं। राजधानी के राजकीय महाविद्यालय कोटशेरा में आयोजित जनमंच के मौके पर कृष्णानगर वार्ड से पूर्व भाजपा पार्षद रजनी ने अपने वार्ड में पानी के कनेक्शन न मिलने का मसला उठाया। उन्होंने महापौर कुसुम सदरेट को निशाने पर लेते हुए कहा कि नगर निगम इस बावत कुछ काम नहीं कर रहा है। इस पर कुसुम सदरेट ने कहा कि निगम में काम हो रहे हैं। सदरेट का बीच में बोलना शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज को नागवार गुजरा और वह अपनी सीट पर खड़े होकर उनके साथ ही मंच पर बैठी कुसुम सदरेट पर भड़क गए। उन्होंने तलख लहजे में कहा कि शिकायतकर्ता अपनी बात कहना चाह रही है और आप उन्हें बात करने से रोक रही हैं। यह कोई तरीका नहीं हैं। समस्याएं सुननी हैं और उनका समाधान निकालना है। यह नजारा देख कर वहां मौजूद सब लोग सन्न रह गए। हालांकि कुसुम सदरेट ने कोई जवाब नहीं दिया व कार्यकम की अध्यक्षता कर रही शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने सुरेश भारद्वाज को चुप कराकर बिठा दिया। इसके बाद महापौर कुसुम सदरेट पूरे कार्यक्रम में कुछ नहीं बोली।

याद रहे विपक्षी पार्टी कांग्रेस पहले ही जनमंच कार्यक्रम को लेकर सरकार पर निशाना साध चुकी है। कांग्रेस इल्जाम लगा चुकी है जनमंच कार्यक्रम लोगों के सामने अधिकारियों को भड़काने का कार्यक्रम बन चुका है। लेकिन जयराम सरकार के मंत्री अपनी ही महापौर पर भड़क गए। पूर्व पार्षद रजनी को भारद्वाज की करीबी बताया जाता है। कई मामलों को लेकर भारद्वाज महापौर से खफा चल रहे हैं।

बीते दिनों ही नगर निगम के सदन में उप महापौर राकेश शर्मा व भाजपा की ही पार्षद आरती के बीच नोकझोंक हो गई थी व इसका वीडियो भी वायरल हो गया। उप महापौर भी भाजपा के ही हैं। भारद्वाज जिस तरह से महापौर पर भड़के उसका भी वीडियो वायरल हो गया है। इस बावत महापौर कुसुम सदरेट ने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी है।